लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 17 जुलाई, 2025
वर्ष : 11 । अंक: 8
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

सही काम करने के लिए समय हर वक्त ही ठीक होता है। - मार्टिन लूथर किंग जूनियर

TODAY WEATHER

DAY	NIGHT
37°	26°
Hi	Low

संक्षेप

राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, 5 मिनट में मिली जमानत

लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर अपनी एक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में मंगलवार को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें महज 5 मिनट के भीतर ही जमानत दे दी। यह मामला 'भारत जोड़ो यात्राÓ के दौरान दिए गए उनके एक बयान से संबंधित है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को 20,000 रुपये के दो जमानती बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। राहुल के वकील प्रांशु अग्रवाल ने जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी दिल्ली से सीधे लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से कोर्ट के लिए रवाना हुए। वह करीब 30 मिनट तक अदालत परिसर में रहे और जमानत मिलने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यह केस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर, 2022 को 'भारत जोड़ो यात्राÓ के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर, 2022 को हुई भारत-चीन सीमा झड़प का जिक्र करते हुए कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल का यह बयान तथ्यों के विपरीत, गुमराह करने वाला और सेना का मनोबल तोड़ने वाला था, जिससे सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंची।

अब 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र, सरकार ला रही ये 8 विधेयक; इनकम टैक्स बिल भी शामिल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में कुल 8 नए विधेयक पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर अब 21 अगस्त तक चलेगा। पहले संसद 12 अगस्त तक ही चलने वाली थी, जिसे बाद में एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोई बैठक नहीं होगी। लोकसभा सचिवालय ने जिन प्रमुख विधेयकों की जानकारी दी है उनमें टैक्स, शिक्षा, खेल, और खनिज नीति जैसे क्षेत्रों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025, भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रख-रखाव) विधेयक, 2025, खनिज और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक (संशोधन), 2025 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इनके अलावा, गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में पुन: प्रतिनिधित्व निर्धारण विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 और आयकर विधेयक, 2025 को पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। संसद की विधायी शाखा के अनुसार, इस बार सभी सांसदों को 'मेंबर्स पोर्टलÓ के माध्यम से ही समन और सूचनाएं भेजी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल- जेल में कटी उम्र और फिर निकले बेकसूर, तो क्यों ना मिले मुआवजा

भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है,

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी को गलत तरीके से लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, तो उसे मुआवजा देने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी लंबे समय से गलत तरीके से कैद किए गए मौत की सज़ा पाए दोषी को बरी करते हुए 15 जुलाई को दिए फैसले में कहा है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अमेरिका के विपरीत, भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवज़ा देने के लिए क़ानूनों का अभाव है। जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विदेशी न्यायक्षेत्रों में, लंबी अवधि की कैद के बाद बरी होने पर अदालतों ने राज्यों को उन लोगों को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है जो सलाखों के पीछे कष्ट सह रहे थे, लेकिन अंततः निर्दोष पाए गए।

मुआवज़े के इस अधिकार को संघीय और राज्य दोनों क़ानूनों द्वारा मान्यता दी गई है।मुआवज़े का दावा करने के दो तरीके हैं। अपकृत्य दावे/ नागरिक अधिकार मुकदमे/ नैतिक दायित्व के दावे और, वैधानिक दावे। पीठ ने कहा कि भारतीय विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विचार किया गया था, लेकिन 'गलत अभियोजन' की उसकी समझ केवल दुर्भावनापूर्ण अभियोजन तक ही सीमित थी, और अभियोजन पक्ष ने गलत कारावास की स्थिति से सीधे तौर पर निपटे बिना, सद्भावना के बिना शुरुआत की।

अदालत ने कहा कि गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, जिससे वह मुआवजे का हकदार हो जाता है, हालांकि इस तरह के मुआवजे का आधार विभिन्न अदालतों में भिन्न हो सकता है। दरअसल हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी यह राय दी थी कि निर्दोष बरी होने का मामला गलत कारावास के लिए मुआवजे के दावे को जन्म दे सकता है।

किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, पीएम धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। मोदी कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं। किसानों के लिए 'पीएम धन-धान्य योजना' को मंजूरी दी है। इसके तहत हर साल 24 हजार करोड़ रुपये से 100 जिलों में कृषि सुधार होगा। Renewal Energy में NTPC को 20 हजार करोड़ रुपये के इंवेस्टमेंट करने को भी हरी झंडी दिखाई है। तीसरे फैसले में सरकार ने एनएलसीआईएल को Renewal Energy में निवेश के लिए 7 हजार करोड़ रुपये मंजूर किया गया है।

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'पीएम धन-धान्य योजना' का मकसद कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में निवेश कर सकेगी NLC

मंत्रिमंडल ने नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट देने को भी मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी। बदले में NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके मिशन की सफलता के लिए बधाई भी दी।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा विज्ञान और नवाचार को अपना करियर बनाएंगे।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी।

मराठी में कराओ अजान, बस बंदूके निकलेंगी... नीतीश राणे का ठाकरे को खुला चैलेंज, हिला पूरा महाराष्ट्र!

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की तस्वीरें सामने आई हैं। मराठी भाषा के छद्म ठेकेदार हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं और उन पर मराठी बोलने का दबाव डाल रहे हैं। पिछले दिनों मराठी भाषा नहीं बोलने पर लोगों की पिटाई की जा रही है। उसे देखने के बाद मानो ऐसा लगता है कि एमएनएस कार्यकर्ता सड़क पर ही मराठी भाषा की पाठशाला चला रहे हैं। अब मंत्री नितेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को खुला चैलेंज दिया है। नितेश राणे ने अब ठाकरे ब्रदर्स को मदरसों में मराठी में अजान कराने की नसीहत दे डाली है। नितेश राणे ने कहा कि अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में कई मदरसे हैं। वहां उर्दू की बजाए आप मराठी शुरू करो उधर। आपकी मेहनत कम हो जाएगी। क्यों मीडिया में आने के लिए नौटंकी की जरूरत है।

राणे उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस मुंबई के कुछ इलाकों में मराठी स्कूल (पाठशालाएँ) शुरू कर रही है। इस कदम की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मराठी स्कूल चलाने की क्या ज़रूरत है? विपक्ष को मुसलमानों से मराठी में अज़ान देने के लिए कहना चाहिए। उर्दू की बजाय मदरसों में मराठी पढ़ाएँ। वरना वहाँ से तो बस बंदूक ही मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, राहुल और खरगे ने पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाए। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों से जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह माँग जायज़ होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना ज़रूरी है कि जहाँ अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में बेमिसाल है। यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में कहा कि आपने स्वयं कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था: 'राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं।'

ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान का बयान

'कल के हथियारों से आज का युद्ध नहीं जीता जा सकता..'

नई दिल्ली, एजेंसी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने हाल के संघर्षों में ड्रोन की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि ये छोटे-छोटे हथियार जंग में पासा पलट सकते हैं।

मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया है कि हमारे भूभाग और हमारी जरूरतों के लिए निर्मित स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणालियां (UAs) और सी-यूएएस क्यों महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के

दौरान बिना हथियार वाले ड्रोन और लॉइटर मुनिशन का इस्तेमाल किया, मगर भारतीय सेना ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया।

जनरल चौहान ने यह भी चेतावनी दी कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी ताकत को कमजोर कर सकती है।

सरकार का ध्यान टियर 2 और टियर 3 शहरों के उद्यमियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार मजबूत किया है। साथ ही, समावेशी प्रयासों और भारत की उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करने की प्रतिबद्धता के माध्यम से विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के उद्यमियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल (एनएसएसी) की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करने के लिए इनोवेशन को आधार के रूप में रेखांकित किया, जिसमें आरएंडडी और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर

दिया गया। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त प्रयास एक जीवंत उद्यमशीलता परिदृश्य को पोषित करने और विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने डीप-टेक स्टार्टअप्स के साथ उनके अनुभवों और अंतर्दृष्टि को समझने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बातचीत की। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, चर्चा में फंडिंग तक बेहतर पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, नियामक सुविधा और वैश्विक बाजार संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीप-टेक इकोसिस्टम को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के तरीकों पर बहुमूल्य सुझाव साझा किए गए। इस संवाद ने उभरती टेक्नोलॉजी और उद्यमियों के लिए एक सहायक और भविष्य के लिए तैयार वातावरण बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

इस बीच, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल, नेशनल स्टार्टअप अवॉर्ड (एनएसए) के पाँचवें एडिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

एनएसए कृषि, क्लीन एनर्जी, फिनटेक, एयरोस्पेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और सुगम्यता सहित कई क्षेत्रों को कवर करता है। प्रत्येक एडिशन में उभरती चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप नई कैटेगरी पेश की जाती हैं।

तेजस मार्क-1ए के लिए मिला इंजन, वायुसेना को मिलेंगे नए फाइटर जेट

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय फाइटर जेट तेजस मार्क-1ए के निर्माण में अब तेजी आएगी। इस लड़ाकू विमान के लिए अमेरिकी कंपनी ने भारत को जेट इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस मार्क-1ए के लिए सोमवार को भारत को जीई-404 इंजन प्राप्त हुआ। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह अमेरिकी कंपनी से मिला दूसरा जेट इंजन है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय विमानन कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) तेजस का निर्माण कर रही है। जानकारी के मुताबिक एचएएल को इस वित्त वर्ष के अंत तक कुल 12 जीई-404 इंजन मिलने हैं। ये सभी

इंजन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1ए में लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी फ्लीट के लिए 83 एलसीए मार्क-1ए लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। इसके लिए वायुसेना ने स्वदेशी लड़ाकू का विकल्प चुना है। इन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह विभिन्न मौकों पर अपना बात भी रख चुके हैं। उन्होंने एलसीए मार्क-1ए की लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में हो रही देरी को स्वीकार किया और इसको लेकर चिंता व्यक्त की थी। माना जा रहा है कि अब वायुसेना को जल्द नए विमानों की आपूर्ति की जा सकेगी। गौरतलब है कि ये स्वदेशी लड़ाकू विमान आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के द्वारा किया जा रहा है। एचएएल ने एलसीए मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर कहा था कि वे एयरफोर्स की चिंताओं से वाकिफ हैं। एचएएल को इंजन का इंतजार था। अब अमेरिका से इंजन मिलना शुरू हो गया है। इस साल (2025-26) में कुल एक दर्जन एविएशन इंजन मिल जाएंगे। ऐसे में वायुसेना को एलसीए मार्क-1ए की सप्लाई जल्द शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस एमके-1ए का ऑर्डर

स्किल इंडिया मिशन के तहत 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया : जयंत चौधरी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा कि देश में छह करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन ने भारत के युवाओं को देश और विदेश, दोनों जगह पर परिवर्तन की एक शक्ति बना दिया है।

उन्होंने बीते 10 साल की इस यात्रा को 'कौशल का दशक' बताया और कहा, पिछले एक दशक में, कौशल विकास, प्रशिक्षुता, उद्यमिता और पारंपरिक व्यवसायों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से एमएसडीई ने 6 करोड़ से अधिक भारतीयों को अपने और देश के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, भारतीय कामगार अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस छिपी हुई क्षमता को पहचाना और स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से इसे राष्ट्रीय दिशा दी। आज, यह नए भारत की एक सशक्त पहचान बन गया है।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी योजनाओं ने 1.64 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जबकि 14,500 से ज्यादा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को गुणवत्ता, प्रशासन और संबद्धता मानदंडों में सुधारों के माध्यम से समर्थन दिया गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, भारत के युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जैसे-जैसे हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, यह उनका कौशल, उत्साह और नवाचार ही है जो हमारे सामूहिक भाग्य को आकार देगा।

स्किल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री ने एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह का भी शुभारंभ किया।

सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में हर राज्य के आईटीआई, कौशल केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।

इस उत्सव का समापन 22 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत स्किल नेक्स्ट 2025' कार्यक्रम के साथ होगा, जिसके दौरान स्कूली बच्चों के लिए एआई कौशल पर एक समर्पित कार्यक्रम सहित प्रमुख कौशल पहलों का शुभारंभ किया जाएगा।

'कार्यालय से बाहर जाइए...' सपा सांसद इकरा हसन के साथ ADM का अभद्र व्यवहार, आरोप पर बैठी जांच

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कैराना सांसद इकरा हसन इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं। सांसद ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एडीएम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। एडीएम ने कथित तौर पर इकरा हसन से कहा, कार्यालय से बाहर जाइए। इसी के बाद एडीएम पर आरोप लगाते हुए सांसद ने सहारनपुर के मंडलायुक्त को इसकी शिकायत की है।

पूरा मामला बीती 1 जुलाई का है। जानकारी के अनुसार, कैराना सांसद इकरा हसन सहारनपुर की छुटमलपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एडीएम से मिलने गई थीं। तभी दोपहर 1 बजे एडीएम से संपर्क करने पर पता चला की वो अभी लंच के लिए गए हुए हैं। लंच के बाद इकरा हसन करीब 3 बजे एडीएम के कार्यालय पहुंचीं।

इकरा के साथ मौजूद छुटमलपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष को एडीएम ने किसी मामले में डांट दिया था। इकरा हसन ने जब बीच में हस्तक्षेप किया तो एडीएम संतोष बहादुर ने इकरा हसन को कथित रूप से अपने कार्यालय से बाहर निकलने के लिए कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि ये उनका दफ्तर है और वो कुछ भी कहने ओर करने के लिए स्वतंत्र है।

इकरा हसन ने ADM की शिकायत की

सपा सांसद इकरा हसन ने एडीएम की एक लिखित शिकायत सहारनपुर के मंडलायुक्त अटल राय के साथ-साथ प्रमुख सचिव नियुक्ति से भी की है। इसके अलावा एक शिकायत पत्र लखनऊ भी भेजा गया है। सपा सांसद की ओर से की गई शिकायत के बाद मंडलायुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश डीएम सहारनपुर मनीष बंसल को दिए हैं।

ADM ने रखा अपना पक्ष

इकरा हसन की तरफ से मामले को उठाए जाने के बाद एडीएम संतोष बहादुर ने भी अपना पक्ष रखा है। एडीएम ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, उन्होंने सांसद के साथ कोई भी अभद्रता नहीं की है, जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। मामले के सामने आने के बाद डीएम सहारनपुर मनीष बंसल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जन प्रतिनिधि के साथ सभ्यता से पेश आया जाए। वहीं, दूसरी तरफ मंडलायुक्त ने कहा, कैराना सांसद की तरफ से अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई है। इस पर जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं।

जीआईसी के प्रधानाचार्य पर गबन के आरोप, हुई पुष्टि

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डॉ मनोज कुमार तिवारी पर शैक्षिक भ्रमण के नाम पर 357955 रुपया गबन करने की पुष्टि हुई। जांच अधिकारी द्वारा जीआईसी के प्रधानाचार्य पर गबन किए गए उपरोक्त शासकीय धन की वसूली करने और विभागीय कार्यवाही करने की गई संस्तुति। बताते चलें शिकायतकर्ता अमित कुमार ने जीआईसी के प्रधानाचार्य मनोज कुमार तिवारी पीईएस पर पुरातन छात्र सम्मेलन में प्राप्त धन, शैक्षिक भ्रमण के नाम पर आवंटित राशि एवं विद्यालय के अन्य मदो के सरकारी धन उपयोग अपने हित में करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी। जिला विद्यालय निरीक्षक रविशंकर ने शिकायतकर्ता के द्वारा जीआईसी के प्रधानाचार्य पर लगाए गए गंभीर वित्तीय आरोपों की जांच के लिए सह जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर और सहायक वित्त एवं लेखाअधिकारी सुल्तानपुर को दो सदस्यीय जांच समिति बनाते हुए अनियमितता की जांच कराई। जांच समिति की रिपोर्ट में प्रधानाचार्य डॉ मनोज कुमार तिवारी ने विद्यालय के विकास के लिए शासन द्वारा आवंटित कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट, टीएलएम ग्रांट, यूथ एवं इको क्लब ग्रांट, कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम ग्रांट, उपचारात्मक शिक्षण ग्रांट, सामुदायिक सहभागिता ग्रांट, एसएमडीसी प्रशिक्षण ग्रांट, खेलकूद सामग्री ग्रांट, गणित क्लब एवं विज्ञान क्लब ग्रांट, कंपोजिट ग्रांट, सामुदायिक सहभागिता ग्रांट, हेल्थ कैंप ग्रांट आदि के भुगतान में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो दूसरी तरफ राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों के शैक्षिक भ्रमण संबंधी भुगतान में प्रधानाचार्य के द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

कांवड़ियों के जत्थे में शामिल डीजे सीज, नौ गिरफ्तार, मानक के अनुरूप नहीं थी ऊंचाई और आवाज भी तेज

आर्यावर्त संवाददाता

गजरौला। नोटिस देने के बाद भी कांवड़ियों के जत्थे में शामिल डीजे संचालक मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस क्रम में स्थानीय पुलिस ने कांवड़ियों के जत्थे में शामिल एक डीजे को पकड़कर सीज किया है।

इस दौरान डीजे पर काम करने वाले नौ लोगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान भी किया है।इससे अन्य डीजे संचालकों में हलचल मच गई।

सावन मास की कांवड़ यात्रा में किसी तरह का हुड़दंग न हो। इसलिए पुलिस ने पहने ही डीजे संचालकों संग बैठक कर उन्हें नोटिस दिए थे। तय किया गया कि था किसी भी डीजे की ऊंचाई 11 फीट से अधिक नहीं रहेगी। बाकी तेज आवाज में डीजे भी नहीं बजेगा। इसके बाद भी डीजे संचालक इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मंगलवार को जनपद सम्भल पुलिस द्वारा अमरोहा पुलिस को सूचना दी थी कि गजरौला थाना क्षेत्र का माधव डीजे असमौली क्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजा रहा है और शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है।

यह डीजे महाकाल बेड़ा कश्यप सेवा समिति के द्वारा हरिद्वार से आ रहे जत्थे में शामिल था। इसके बाद पुलिस ने माधव डीजे को हसनपुर रोड से चौपला के पास पकड़ लिया।

पूछताछ में यह डीजे मुहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना बछरायूं का पता चला। फिर पुलिस ने डीजे को सील करते हुए डीजे पर काम करने वाले नौ लोगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया है। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि आवाज का मानक 70 डेसिबल निर्धारित है। मगर, अनुभव के आधार पर यह डीजे लगभग 300 डेसिबल से अधिक बज रहा था।

गर्लफ्रेंड ने पूछा एक सवाल– अपना वादा तो याद है ना, शादी से कहीं... बॉयफ्रेंड का जवाब सुन दौड़ी–दौड़ी पहुंची थाने

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। दो प्रेमियों में प्यार कब तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी इश्क का फितूर सिर चढ़कर बोलता है, तो भी लोग प्यार से एक समय बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ यूपी के गाजियाबाद की रीना के साथ। जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिसने उसे शादी का सपना दिखाया और कई सारे वादे किए। वही ऐन वक्त पर शादी से मुकर गया। रीना अपने बॉयफ्रेंड की इन तीखी बातों को सुनकर अभी भी सदमे में है।

मगर उसने प्रेमी को सबक सिखाने का ठान लिया था। रीना ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने फिर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रीना एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। वो परिवार के साथ ट्रोनिका सिटी में रहती है और कॉलेज में पढ़ाई करती है। खाली वक्त में वो सोशल मीडिया भी चलाती है। बस यहीं उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर 21 साल के मनीष से हुई।

मनीष ने बताया कि वो एक कंपनी में नौकरी करता है। दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज किए। दिन रात एक दूसरे से बात करने लगे। फिर यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों अक्सर बाहर मिलने जुलने लगे। आरोप है कि मनीष ने रीना को झूठे सपने दिखाए। कहा- मैं तुमसे शादी करूंगा। रीना भी उसकी बातों में आ गई। मनीष के कहने पर उसने कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाए।

रीना के परिवार को भी इसकी भनक लग गई। रीना ने तब परिवार को भरोसी दिलाया कि मनीष उससे शादी करेगा। यह बात मनीष को पता चली तो वो रीना से कन्नी काटने लगा। रीना को ये सब महसूस तो हो रहा था, पर वो पहले उससे कुछ नहीं बोली। उसे लगा कि शायद मनीष नौकरी के चलते उसे वक्त नहीं दे पा रहा। मगर दिन बीते और मनीष का रवैया और ज्यादा बदलने लगी।

रीना को लगा बड़ा झटका

फिर एक दिन रीना ने मनीष से पूछ ही डाला- तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या कोई और तुम्हारी जिंदगी में आ गई है? मनीष ने कहा- नहीं मेरी जिंदगी में फिलहाल कोई नहीं है। रीना ने पूछा- तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। घरवालों को भी इसका पता है। सब जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम शादी तो करोगे ना मुझसे? धोखा तो नहीं दोगे? इसका जो जवाब मनीष ने दिया उसे सुनकर रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई।

शादी से मुकर गया प्रेमी

मनीष बोला- नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि तुम उनकी बहू बनो। इसलिए तुम अब मुझसे दूर चली जाओ। मुझसे कोई कॉन्टेक्ट मत रखना। रीना ने उसे समझाने की खूब कोशिश की। मगर मनीष अपने फैसले से जस से तस न हुआ। फिर रीना ने घर वालों को ये बात बताई। 29 जून को वो सीधे थाने पहुंची। वहां पुलिस को आपबीती सुनाई। बोली- मनीष ने मेरा इस्तेमाल किया है। पुलिस ने फिर मनीष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन यह कहानी हमें सबक सिखाती है कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्यार करो लेकिन उसने अपनी हदें पार न करो। नहीं तो अंजाम कभी-कभी बुरा होता है। बहरहाल रीना को उम्मीद है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा।

डीएम ने जनसुनवाई में सुनी फरियादियों की समस्याएं

प्रयागराज। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने बुधवार को कलेक्टेट परिसर के जनमिलन कक्ष में जनसुनवाई करते हुए जिले भर से आये हुए जनसामान्य की समस्याओं को एक-एक करके सुना एवं उनके द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए शिकायती एवं मांग पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर प्रकरण से अवगत कराते हुए उनके शिकायती व मांग पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए उस पर उचित कार्यवाही कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित भी किया है। जिलाधिकारी प्रतिदिन की भांति बुधवार को भी जनसुनवाई में लोगो की जन-शिकायतों को सुनते हुए उनका निस्तारण कर रहे थे। एडीएम नमामि गंगे के द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, एसडीएम सोरांव, भूमि अध्याप्ति अधिकारी व यूपीडा के अधिकारियों एवं अन्य सम्बंधित से वीडिओ कांफ्रेंसिंग कर सम्बंधित प्रकरण पर शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराये जाने के लिए कहा गया है।

29 बिजली के पोल से चोरों ने उड़ा दिए तार, दो दर्जन गांव अंधेरे में डूबे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मथुरा। फरह के भीमनगर स्थित 33 केवी बिजली घर से चुरमुरा होते हुए मंडोरा सब स्टेशन तक जा रही मुख्य लाइन से चोरों ने 29 पोल से बिजली के तार उड़ा दिए। इस बड़ी चोरी की वारदात से क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांव अंधेरे में डूब गए हैं। ग्रामीणों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

चोरों ने मंगलवार रात सुनियोजित तरीके से चुरमुरा होते हुए मंडोरा सब स्टेशन तक जा रही मुख्य लाइन के 29 बिजली के खंभों से तार काटकर गायब कर दिए। बिजली विभाग को जब बुधवार सुबह आपूर्ति बाधित होने की सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची।

सैकड़ों मीटर तक तार गायब देखकर उड़ गए होश

सैकड़ों मीटर तक गायब तार देख बिजली कर्मियों के होश उड़ गए। चोरी हुए तारों की कीमत लाखों रूपये बताई जा रही है। सूचना पर फरह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी इस प्रकार की बिजली तार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।ग्रामीणों ने बिजली विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं।

धूमधाम से मनाया गया सीएससी दिवस, सेवाओं की दी गई जानकारी

सुलतानपुर। विभिन्न कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) पर सीएससी दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सीएससी केंद्र संचालकों ने स्थानीय नागरिकों को केंद्रों पर उपलब्ध विभिन्न डिजिटल सेवाओं के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फार्मर रजिस्ट्री, डीजीपे, पीएम फसल बीमा योजना, रेलवे एवं फ्लाइट टिकट बुकिंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट सेवा, बिजली बिल भुगतान, एवं अन्य अनेक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। सीएससी संचालक ओम प्रकाश शुक्ला,मो इमरान, धनंजय पाठक, एवं जय प्रकाश शुक्ला ने बताया कि "हर वर्ष हम सीएससी दिवस मनाकर आमजन को डिजिटल इंडिया मिशन से जोड़ने का कार्य करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाएं सरलता से पहुंचाई जा सकें। इस अवसर पर सीएससी जिला प्रबंधक विनोद यादव एवं सुनील ने बताया कि "सीएससी केवल एक सेवा केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण भारत का डिजिटल प्रवेश द्वार है।

सपा में खुलकर सामने आई गुटबाजी... पूर्व जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव समेत चार पर जानलेवा हमले का आरोप, मुकदमा दर्ज

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। समाजवादी पार्टी में जिले और शहर के वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार शाम सपा के कार्यकर्ता ताजगंज निवासी सत्यभान यादव ने अपनी ही पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव समेत चार पर जानलेवा हमला कराने और धमकाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव बुढाना निवासी सत्यभान यादव ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को प्रार्थना पत्र देकर अपनी व अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसे बीते पांच दिनों से लगातार मोबाइल कॉल, वाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

दो नंबरों से किए धमकी भरे कॉल

सत्यभान ने आरोप लगाया कि आठ जुलाई को दो मोबाइल नंबरों से उसे धमकी भरे कॉल किए गए। धमकी देने का आरोप सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव, लखेन्द्र यादव उर्फ लख्खो, संदीप यादव और पवन यादव पर है। सत्यभान के अनुसार इन सभी ने अपशब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी दी।

अज्ञात नकाबपोशों ने किया हमला

पीड़ित के मुताबिक 10 जुलाई की शाम करीब सात बजे जब वह खेत पर गया, तब चार अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। उनके चेहरे कपड़ों से ढके थे। आरोपियों ने पीटते हुए कहा कि अगर राम सहाय यादव के सामने राजनीति की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागा और घर पहुंचा। डर की वजह से वह तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दे सका। सत्यभान ने कहा कि हमलावरों ने जाते-जाते चेतावनी दी कि यदि पुलिस में शिकायत की तो उसके परिवार को भी खत्म कर देंगे।

अखिलेश यादव से शिकायत पर हुई रार

सूत्रों की मानें तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुटबाजी को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद सभी जिले और महानगर की कमेटियों को भंग किया गया था। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इसको लेकर कई दिनों से गुटबाजी चल रही है। कुछ नेताओं के बीच अपने चाहतों को चुनाव लड़ाने का लालच दिया गया है और इसके कारण भी मनमुटाव हो गए हैं।

बंद पड़े जिम की छत पर सात युवक करते थे चलाते थे फैक्ट्री, पुलिस को मिली धंधे की खबर तो उड़ गए होश

आर्यावर्त संवाददाता

अमरोहा। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पांच तस्करों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। यह फैक्ट्री क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी अड्डे के पास बंद पड़े जिम के ऊपर सोलर पैनल के नीचे चल रही थी। भारी संख्या में पुलिस ने बने व अधबने हथियार बरामद किए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने पुलिस टीमों को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया है।

मंगलवार की दोपहर कार्यालय पर पूरे मामले का राजफाश करते हुए एसपी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे शादाब अली व सुमित कुमार निवासी गांव माछरा भगवानपुर कोतवाली हसनपुर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक रिवाल्वर देशी 32 बोर, पांच तमंचा 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, एक तमंचा 315 बोर अधबना, 50 कारतूस 315 बोर बिना मार्का तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए।

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने बताया कि अवैध रूप से धन कमाने के लिए वह अवैध शस्त्र बनाकर दीपक निवासी मंझौला थाना गजरौला, वंश उर्फ गोलू निवासी सरकड़ा थाना बछरायूं, गौरव निवासी रतनपुर कला, थाना पाकबड़ा मुरादाबाद, नागेंद्र सूदनपुर थाना रजबपुर व अंकुश निवासी हाफिजपुर थाना रजबपुर को तमंचे व कारतूस बेच देते थे। असलहों को पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी की जा रही थी। इस अवसर पर सीओ दीप कुमार पंत भी मौजूद रहे।

ग्रेजुएट है सुमित, शादाब आठवीं पास

बावनखेड़ी में असलहा फैक्ट्री संचालित करते पकड़ा गया सुमित ग्रेजुएट है। वह रेलवे में भर्ती होने की भी तैयारी कर रहा था लेकिन, पैसा कमाने के लालच में उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया।

शादाब अली कक्षा आठ तक पढ़ा लिखा है। अवैध शस्त्र बनाकर वह दोनों क्षेत्र में ही अपने परिचितों को बेच देते थे। एक तमंचा तीन से लेकर पांच हजार तक बेचते देते थे।

तस्करों से भी बरामद किए असलहे

कोतवाली हसनपुर पुलिस व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने के बाद आरोपितों द्वारा असलहे व कारतूस खरीदने वालों के नाम सामने बताए गए। गजरौला, रजबपुर व डिडौली पुलिस ने पांचों तस्करों को धर दबोचा। उनके पास से पांच तमंचा व 12 जिंदा कारतूस बरामद किए।

पहले भी कई बार पकड़ी गईं अवैध शस्त्र फैक्ट्री

सर्किल क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़े जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई जगह फैक्ट्री पकड़ी गई हैं।

24 मार्च 2024, को थाना डिडौली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी थी।

वर्ष 2020 में आदमपुर पुलिस ने काई मुस्तकम के जंगल में असलहा फैक्ट्री पकड़कर उपकरण व बने व अधबने शस्त्र बरामद किए थे।

वर्ष 2014 में आदमपुर पुलिस ने बबूल के वन में असलहा फैक्ट्री पकड़ी थी। आरोपितों के कब्जे से नौ बने हुए व एक अधबना तमंचा बरामद किया था।

इसके अलावा सैदनगली पुलिस ने क्षेत्र के एक खंडहर भवन में दो साल पहले शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी थी।

रहरा पुलिस ने क्षेत्र के गांव गंगवार के जंगल में शस्त्र फैक्ट्री संचालित किए जाने का भंडाफोड़ किया था।

विद्यालय मर्जर के विरोध में शिक्षकों ने सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों की कम छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों का पेयरिंग/मर्जर किए जाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर तेज़ी से चल रही है, जो कि शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 एवं बाल अधिकारों की भावना के सर्वथा विपरीत है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अनिवार्य है। वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष एवं शिक्षकों का कहना है कि विद्यालयों की स्थापना नियमानुसार हुई थी, लेकिन बीते वर्षों में निजी विद्यालयों को नियमों के विरुद्ध मान्यता देना, शिक्षक विहीन विद्यालयों में नियुक्ति न होना, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराना जैसे कारणों से कुछ स्थानों पर छात्र संख्या घटी है। इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वे लगातार गांवों में जाकर अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को विद्यालय में ला रहे हैं। सरकार को विद्यालय में आधारभूत संसाधन सुधारने चाहिए थे और 1 किलोमीटर के दायरे में चल रहे प्राइवेट प्राथमिक विद्यालयों को बंद कराया जाना चाहिए था और 3 किलोमीटर के दायरे में चल रहे प्राइवेट जूनियर विद्यालयों को बंद किया जाना था तब हमारी संख्या कभी काम नहीं होती लेकिन सरकार मानक को ताख में रखकर प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देती जा रही है वहीं यशस्वी विधायक कादीपुर ने आश्वासन दिया कि हम आपके सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक अवश्य पहुंचाएंगे और उसका उचित निस्तारण किया जाएगा। और वहीं जिला मंत्री राम आशीष मौर्य ने कहा कि यदि विद्यालयों को दूरस्थ स्थानों में मर्ज कर दिया गया तो गांव और गरीब परिवारों के छोटे बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

नगर पालिका कार्यालय पर ओआरएस कार्नर की स्थापना

नगर पालिका चेयरमैन फात्मा रज़ा ने किया उद्घाटन

आर्यावर्त संवाददाता

बदायूं। जनपद में आगामी 31 जुलाई तक चलने वाले डायरिया रोको अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में ओआरएस कार्नर की स्थापना की गयी है, जिसका उद्घाटन बुधवार को नगर पालिका चेयरमैन फात्मा रज़ा ने किया।

इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन फात्मा रज़ा कहा कि भीषण गर्मी और बारिश के दौरान डायरिया के मामले बढ़ जाते हैं। डायरिया का सही इलाज ओआरएस का घोल और जिंक के टेबलेट हैं, जिन्हें उम्र के अनुसार निश्चित अवधि तक लेना बहुत जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक डायरिया रोको अभियान चलाया जा रहा है। डायरिया रोको अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू भी सहयोग कर रहे हैं। अभियान की इस साल की थीम- "डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान" तय की गयी है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन और जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है।

डायरिया रोको अभियान के प्रभावी संचालन एवं अधिक से अधिक जनसामान्य तक स्वास्थ्य सन्देश पहुंचाने के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर ओआरएस व जिंक कार्नर स्थापित किये जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका कार्यालय के प्रमुख स्थान पर यह कार्नर स्थापित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि बच्चे को दिन भर में तीन या तीन से अधिक बार दस्त हो तो समझना चाहिए कि बच्चा डायरिया से ग्रसित है और ऐसे में उसको तत्काल ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी और नमक की कमी न होने पाए, साथ ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर सम्पर्क करना चाहिए। इस मौके पर कार्यालय अधीक्षक खालिद अली, मुख्य खाद्य निरीक्षक मो. तैयब अली, खाद्य निरीक्षक केशव गंगवार, लिपिक नावेद इकबाल गनी, सचिन सक्सेना, सूर्य प्रकाश सक्सेना, महेश बाबू, जहांगीर बाबू, सुमित सिंह, शहजाद सलीम, पैरोकार मनोज कुमार, सुरेंद्र कुमार, गौशाला प्रभारी राकेश सोनकर तथा पीएसआई इंडिया से शशांक दुबे और दानिश वर आदि मौजूद रहे।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, भयापुरवा की छात्राओं ने जिला स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में दिखाई बेहतरीन प्रतिभा

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, भयापुरवा भिनगा की छात्राओं ने हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रतियोगिता 14 और 15 जुलाई को स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा में संपन्न हुई, जिसमें जूनियर बालिका वर्ग की छात्राओं ने बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के विभिन्न वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया।बास्केटबॉल के सेमीफाइनल में भयापुरवा की छात्राओं ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय को हराकर फाइनल में जगह बनाई और वहां स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रावस्ती को पराजित कर विजेता बनीं। एथलेटिक्स में भी छात्राओं ने अपने दमदार प्रदर्शन से अलग-अलग स्पर्धाओं में पदक हासिल किए।

केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सौर ऊर्जा से बढ़ी महिलाओं की आमदनी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ग्रामीण रोजगार का सशक्त माध्यम बनाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित टेक होम राशन (टीएचआर) इकाइयों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर न केवल विद्युत व्यय में कमी लायी जा रही है, बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि वे अपने उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा विभिन्न जिलों में टीएचआर इकाइयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अब सौर ऊर्जा की सहायता से बिजली का खर्च घटाया जा रहा है।मिशन निदेशक दीपा रंजन के अनुसार, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के समन्वय से 49 टीएचआर इकाइयों पर 75 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे हाल ही में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृति मिली। अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 25 इकाइयों पर सौर ऊर्जा संयंत्र पूर्ण रूप से चालू हो चुके हैं। इन 25 इकाइयों में से 13 को प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में कुल 587.01 लाख रुपये, 6 इकाइयों को प्रथम किश्त के रूप में 135.60 लाख रुपये, यानी कुल 722.60 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है। बाकी 6 इकाइयों को द्वितीय किश्त के भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है।अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीना ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए 75 केवीए तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। सामान्य इकाइयों को लागत का 50 प्रतिशत, जबकि महिला स्वामित्व वाली इकाइयों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।उल्लेखनीय है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और ये अधिकतर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा के बाहर संचालित होते हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा के माध्यम से इन इकाइयों को सशक्त बनाना न केवल ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल कदम है।इस परियोजना से जहां महिला उद्यमियों को लाभ हुआ है, वहीं सरकार की 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' की दिशा में एक अहम पहल भी सिद्ध हो रही है। उप मुख्यमंत्री मौर्य की इस पहल से प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिल रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिल रहा है।

भू–सम्पदा क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की दिशा में बड़ा कदम, यूपी रेरा ने सौंपे प्रमाण पत्र

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आज भू-सम्पदा क्षेत्र को पारदर्शी, जिम्मेदार और उपभोक्ता हितों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तीन बैचों—ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें बैच के सफल एजेंट्स को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह कार्यक्रम रेरा की ओर से चलाए जा रहे चार दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। लखनऊ में आयोजित समारोह में रेरा अध्यक्ष संजय आर. भूसरेड्डी ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र सौंपते हुए कहा कि "पहले रेरा एजेंट बनने के लिए किसी विशेष योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी, जिससे उपभोक्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब रेरा की नई व्यवस्था के तहत एजेंट्स को प्रशिक्षण और परीक्षा दोनों अनिवार्य कर दिए गए हैं, ताकि केवल योग्य और जिम्मेदार एजेंट ही इस प्रणाली में शामिल हों।"रेरा अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 15 बैचों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। प्रशिक्षण के अंतर्गत रेरा से जुड़े कानून, उपभोक्ता अधिकार, एजेंट की जिम्मेदारियां, एग्रीमेंट की प्रक्रिया, और विवाद समाधान जैसे अहम विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत आयोजित परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को ही प्रमाणित रेरा एजेंट बनने की पात्रता मिलती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु रेरा ने दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं—एक लखनऊ में और दूसरा गौतमबुद्ध नगर में। इन केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता के साथ सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ग्राम सेवई में 4 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त, नगर निगम की सख्त कार्रवाई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त और नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए मंगलवार को एक सघन अभियान चलाया गया। यह अभियान अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह द्वारा गठित विशेष टीम की निगरानी में ग्राम सेवई, तहसील सरोजनी नगर में सफलतापूर्वक संचालित हुआ।इस कार्रवाई में नगर निगम लखनऊ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर हुए अस्थायी कब्जों को हटाने के लिए बुलडोज़र चलाया। यह पूरी कार्यवाही प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) संजय यादव की निगरानी और नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार के नेतृत्व में की गई। साथ में लेखपाल संदीप कुमार और अजीत तिवारी तथा थाना सुशांत गोल्फ सिटी से पहुंची पुलिस टीम ने भी मुस्तैदी से सहयोग किया।अभियान के तहत ग्राम

सेवई की खसरा संख्या 829/0.1910 ऊसर भूमि में से 0.155 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वर्षों से अवैध रूप से किए गए निर्माण को मौके पर जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने संयम और शांति के साथ पूरी प्रक्रिया को सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया। अधिकारीगणों ने मौके पर स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं बनने दी।नगर निगम के अनुसार, मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है। यह भूमि अब पुनः शासन के नाम सुरक्षित दर्ज कर ली गई है।इस कार्रवाई को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या समूह सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक एवं आवासीय सहायता देने की घोषणा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। आवास विकास क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी सेक्टर-9 में मंगलवार को हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में गोपाल खेड़ा निवासी युवक अनुज की असमय मृत्यु हो गई। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। इस हादसे के बाद नगर निगम लखनऊ ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार को त्वरित आर्थिक सहायता, आवास एवं रोजगार देने का आश्वासन दिया है।नगर निगम ने तुरंत पीड़ित परिवार को ₹4,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की है और साथ ही ₹5,00,000 की अतिरिक्त मदद के लिए मुख्यमंत्री को संस्तुति भेजी जा रही है। इसके अलावा परिवार को डूडा योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि परिवार का कोई सदस्य रोजगार चाहता है तो नगर निगम की कार्यदायी संस्था उसके योग्यता के अनुसार सेवायोजन के लिए भी पहल करेगी।इस दुखद घटना पर माननीय महापौर सुषमा खर्कवाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपर नगर आयुक्त ललित कुमार और अरुण कुमार गुप्त को निर्देश दिए कि वे पीड़ित परिवार से मिलकर हर प्रकार की सहायता सुनिश्चित करें। बुधवार को अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, अरुण कुमार गुप्त, उद्यान अधीक्षक शशिकांत शशि तथा जोनल अधिकारी अजीत राय ने पीड़ित परिवार के घर जाकर शोक व्यक्त किया और आर्थिक सहायता की औपचारिकताएं पूरी कीं।नगर निगम ने बताया कि दुर्घटना के दिन उद्यान विभाग की टीम स्थानीय शिकायतों के आधार पर वृक्षों की नियमित छंटाई कर रही थी। छंटाई स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत रस्सी से बैरिकेडिंग की गई थी।

, छात्राओं ने प्रकृति के प्रति समर्पण का दिया संदेश

बीबीएयू के सावित्रीबाई फुले छात्रावास में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में मंगलवार, 16 जुलाई को 'वृक्षारोपण पखवाड़ा' के अंतर्गत विशेष वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के बागवानी एवं सौंदर्यीकरण अनुभाग के तत्वावधान में और कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।इस अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की भावनात्मक पहल के तहत छात्रावास परिसर में पौधारोपण किया गया। छात्राओं ने स्वयं अपने हाथों से पौधे लगाकर उन्हें अपनी माताओं को समर्पित किया, जिससे न सिर्फ पर्यावरण

संरक्षण का संदेश प्रसारित हुआ, बल्कि मातृत्व के प्रति सम्मान और प्रकृति के साथ भावनात्मक जुड़ाव का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ।कार्यक्रम में बागवानी एवं सौंदर्यीकरण अनुभाग की अध्यक्ष प्रो. दीपा एच. द्विवेदी के सहयोग से आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से डॉ. नमिता जैसल और हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर डॉ. समीर दीक्षित की उपस्थिति रही। उन्होंने उपस्थित छात्राओं और शिक्षिकाओं को पौधों की प्रजातियों, उनके रखरखाव और पर्यावरणीय महत्त्व के बारे में जानकारी दी।इस वृक्षारोपण अभियान में छात्राओं और शिक्षिकाओं ने मिलकर कई प्रकार के पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि छात्राओं में पर्यावरणीय चेतना को जागृत करना और प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना भी था।बागवानी अनुभाग की ओर से लगाए गए पौधों की देखरेख के लिए आवश्यक सुझाव और मार्गदर्शन भी दिया गया, ताकि ये पौधे दीर्घकालिक रूप से विश्वविद्यालय परिसर के पर्यावरण में योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी।

129 ग्राम स्मैक व 300 पुड़िया के साथ दो गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की सख्ती रंग ला रही है। मंगलवार देर रात थाना मडियांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में स्मैक व 300 पुड़िया बरामद की गई हैं। पुलिस ने तस्करों के पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है जिसका उपयोग वे तस्करी में कर रहे थे।पुलिस टीम 16 जुलाई की तड़के भिठौली तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक काले रंग की बाइक पर मड़ियांव की ओर से स्मैक लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और दोनों युवकों को मौके पर ही दबोच लिया।गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मोहम्मद कबीर (21 वर्ष) और मोहम्मद इरफान (20 वर्ष), निवासी ग्राम टिकरा उस्मा, थाना जैतपुर, जनपद बाराबंकी के रूप में हुई है। तलाशी में उनके पास से कुल 129 ग्राम स्मैक और 300 पुड़िया बरामद हुईं। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (हीरो स्प्लेंडर, यूपी 41 बीए 7734) भी पुलिस ने जब्त कर ली।

पुलिस के अनुसार, दोनों अभियुक्त सस्ते दामों पर स्मैक बाराबंकी से लाकर लखनऊ के विभिन्न इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। नशे की बढ़ती मांग और मुनाफे की लालच में दोनों ने यह अवैध धंधा अपनाया था। दोनों का व्यवसाय मजदूरी बताया गया है, लेकिन नशे के कारोबार ने उन्हें अपराध के रास्ते पर उतार दिया।गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना मडियांव में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में अन्य संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।

थाना महानगर पुलिस ने दो शातिर चोरों को धर दबोचा, छह चोरी की बाइकें बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थाना महानगर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम कसते हुए पुलिस ने एक बड़ी सफलता दर्ज की है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से छह चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सलमान पुत्र स्व. मोहम्मद रशीद और नफीस पुत्र हफीज, दोनों निवासी उमराव हाता, निशातगंज, लखनऊ के रूप में हुई है। इनमें से एक अभियुक्त नफीस पूर्व में भी चोरी के एक मामले में जेल जा चुका है।पुलिस को यह कामयाबी उस वक्त मिली जब 15 जुलाई की शाम थाना महानगर की टीम गोल मार्केट चौराहे पर नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान दो युवक एक मोटरसाइकिल (UP32FY0295) को संदिग्ध अवस्था में पैदल खींचते हुए नजर

आए। पूछताछ के दौरान वे गाड़ी से संबंधित कोई भी संतोषजनक दस्तावेज नहीं दिखा सके। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल की जांच की तो पता चला कि वह वाहन चोरी की है और इस संबंध में पहले से ही थाना महानगर में एफआईआर दर्ज है।पुलिस ने तत्काल दोनों युवकों को हिरासत में लिया और जब सघन पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त बाइक को तीन दिन पहले चोरी किया था और क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी चोरी की गई बाइकें छिपा रखी हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने अकबरनगर, फातिमा क्रासिंग और न्यू हैदराबाद से पांच अन्य चोरी की बाइकें बरामद कर लीं। इन बाइकों में से एक की नंबर प्लेट (UP32FT4003) बदली गई थी ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके।पूछताछ में यह भी सामने आया कि दोनों अभियुक्त पेशेवर वाहन चोर हैं और नशे की लत के कारण उन्होंने चोरी को अपना स्थायी जरिया बना लिया था।

नीति आयोग की पहल पर "विकसित यूपी 2047" कार्यशाला में तैयार हो रही प्रदेश के समग्र विकास की रणनीति

लखनऊ। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा विकसित 'राज्य फॉर विकसित भारत/2047' कार्यक्रम के अंतर्गत आज योजना भवन में "विकसित यूपी 2047" विषय पर एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु एक रणनीतिक विकास ब्लू प्रिंट तैयार करना है, जो राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा को स्पष्ट रूप से निर्देशित करेगा।कार्यशाला की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वीवीआर सुब्रह्मण्यम ने की। इस दौरान नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने "विकसित भारत 2047" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश के संभावित विकास मार्गों, प्राथमिकताओं तथा चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की।

लखनऊ पुलिस ने टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर ठगों से जुड़े अंतरराज्यीय गैंग का किया भंडाफोड़

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। देशभर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम और क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसे नामों पर हो रही करोड़ों की ऑनलाइन ठगी के मामलों में लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम सेल और थाना साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को 8 शातिर अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जो टेलीग्राम एप के माध्यम से चीनी साइबर ठगों के संपर्क में रहकर पूरे देश में ठगी की रकम को USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशी ठगों को भेजते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1.75 लाख रुपये नकद, 12 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, दो पासबुक और तीन चेकबुक बरामद की गई हैं।इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देश पर किया गया। अभियान का संचालन संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अमित वर्मा, पुलिस उपायुक्त (अपराध) कमलेश कुमार दीक्षित, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) रल्लापल्ली बसंत कुमार और सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम ऋषभ यादव के पर्यवेक्षण में हुआ। कार्रवाई को साइबर क्राइम सेल व थाना साइबर क्राइम की टीमों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया।गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे इंस्टाग्राम के माध्यम से टेलीग्राम एप के चीनी ग्रुप्स जैसे 32-105/1, 32-105/3, 32-105/5 PAYGir G0 ! से जुड़ते थे। इसके बाद चीनी साइबर अपराधी उन्हें भारत में रम्यूल बैंक अकाउंटर का इंतजाम करने का निर्देश देते थे। आरोपी लखनऊ और आसपास के जनपदों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते और उनसे पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और नेट बैंकिंग की जानकारियां ले लेते थे। ये सारी जानकारी वे चीनी ठगों को भेज देते थे।इन बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम भेजी जाती थी, जिसे आरोपी एटीएम या चेक के जरिए तुरंत निकाल लेते थे ताकि खाता फ्रीज होने से पहले रकम निकल जाए। फिर यह रकम क्रिप्टोकरेंसी (USDT) में बदलकर चीनी ठगों के वॉलेट में भेज दी जाती थी। कमीशन की रकम आपस में बांटकर बचे हुए पैसों से ये दोबारा USDT खरीद लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिन बैंक खातों का उपयोग किया गया, उनके खिलाफ देशभर के राज्यों—हरियाणा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि—से लगभग छह करोड़ रुपये की ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। संबंधित राज्यों से संपर्क कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राहुल सोनकर, मो. सलमान, देवांश शुक्ला, राज रावत, फैज़ान, मोजिज़ रिज़वी, अंकित यादव और करन रावत शामिल हैं, जिनकी उम्र 19 से 28 वर्ष के बीच है और सभी लखनऊ के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। ये सभी शिक्षित और तकनीक से भलीभांति परिचित हैं। पुलिस के अनुसार, इनके गिरोह में और भी सदस्य हो सकते हैं, जिनकी पहचान की जा रही है।इस मामले में थाना साइबर क्राइम में बीएनएस की धारा 317(2)/318(4)/61(2)(बी) और आईटी एक्ट की धारा 66सी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान सोशल मीडिया ग्रुप, वेबसाइट या मोबाइल लिंक पर भरोसा न करें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मिलने वाले वर्क फ्रॉम होम ऑफर या डिजिटल निवेश योजनाओं से दूर रहें।

बिहार तो बस झांकी है, पूरा देश बाकी है!

बिहार में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र निवासी प्रमाणपत्र पर या तो जन्म की तिथि नहीं होती या निवास का पता नहीं लिखा होता है। ये दो चीजें ही मतदाता बनने के लिए चाहिए। फिर इन तीन में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर कोई मतदाता कैसे बन पाएगा? इसके अलावा दो दस्तावेज हैं एनआरसी और फैमिली रजिस्टर। एक समय था जब भारत के चुनाव आयोग की दुनिया भर में साख थी। ऐसी साख कि दुनिया के जिन देशों में संसदीय लोकतंत्र पहले से है या जिन्होंने बाद में उसे अपनाया, वे सारे भारतीय चुनाव आयोग को निमंत्रण देकर अपने यहां बुलाते थे और अनुरोध करते थे कि वह आए और उनके यहां के चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करे कि निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जाते हैं। ऐसे अनुरोधों पर भारत का चुनाव आयोग अपने अधिकारियों का दल संबंधित देशों में भेजता भी था। कई देश भारत में चुनाव के समय अपने यहां के चुनाव अधिकारियों को भारत के दौरे पर भेजते थे, यह देखने के लिए भारत का चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराता है। यह सिलसिला अब बंद हो चुका है, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग अपनी साख पूरी तरह गंवा चुका है।

कहने को तो चुनाव आयोग अभी भी एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है लेकिन पिछले एक दशक से वह व्यावहारिक तौर पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक विभाग में तब्दील हो गया है। इसकी ताजा मिसाल बिहार में देखी जा सकती है, जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया है, जो स्पष्ट रूप से एक तर्कहीन और हास्यास्पद तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। चूंकि चुनाव आयोग की नीयत साफ नहीं है, इसलिए उसने अपनी इस कवायद पर बिहार के विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की आपत्तियों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की राह आसान करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहे इस तमाशे का स्पष्ट मकसद बड़ी संख्या में गरीब, वंचित अल्पसंख्यक तबके के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग बिहार के लोगों से उनकी नागरिकता का प्रमाणपत्र मांग रहा है। इस सिलसिले में उसका कहना है कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज करा सकता। इन तीन के अलावा चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनके आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। इन 11 में से कोई एक दस्तावेज मतगणना प्रपत्र के साथ जमा कराना है। इनमें सरकारी नौकरी या संपत्ति आदि के दस्तावेजों को छोड़ दें तो कई दस्तावेज ऐसे हैं, जिन्हें बनवाने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना होता है। यानी आधार कार्ड के सहारे कोई व्यक्ति जो दस्तावेज बनवाएगा, उनसे वह मतदाता बन सकता है लेकिन सीधे आधार कार्ड के आधार पर मतदाता नहीं बन सकता।

गौरतलब यह है कि बिहार में आवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड ही एकमात्र दस्तावेज है। यानी कोई आधार लेकर जाएगा तो उसका आवास प्रमाणपत्र बन जाएगा और वह आवास प्रमाणपत्र चुनाव आयोग की ओर से वांछित 11 दस्तावेजों में से एक है। यानी उसे जमा करा कर कोई भी व्यक्ति मतदाता बन सकता है। पिछले 15 दिनों में लाखों लोगों ने आधार कार्ड के जरिए अपना आवास प्रमाणपत्र बनवाने का आवेदन किया है। इनमें से 10 फीसदी के भी प्रमाणपत्र 25 जुलाई तक नहीं बन पाएंगे। इससे जाहिर है कि चुनाव आयोग ने लोगों को परेशान करने के लिए यह कवायद शुरू की है। अगर आधार कार्ड के जरिये आवास प्रमाणपत्र बन सकता है और उससे मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकता है तो फिर सीधे आधार कार्ड के दम पर मतदाता बनाने में क्या समस्या है? मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर जिन मान्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने की इजाजत है उनमें आधार और मनरेगा कार्ड दोनों हैं। लेकिन बिहार में इन दोनों के आधार पर मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इन दोनों के आधार पर देश के दूसरे हिस्सों में मतदाता पहचान पत्र बनाया जा सकता है।

कायदे से चुनाव आयोग को अगर यह काम करना ही था तो इसकी शुरुआत जनवरी में करनी थी, मतदाताओं को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था और राजनीतिक दलों को भी भरोसे में लेना था। 22 साल पहले 2003 में भी चुनाव आयोग ने यह काम किया था, जिसमें उसे दो साल लगे थे लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने वही काम करने के लिए एक महीने की अवधि निर्धारित की है। जाहिर है कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो कुछ कर रहा है, उसके पीछे उसकी नीयत साफ नहीं है।

मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है

ललित गर्ग

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्वेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है। अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है? भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि 'जो सरकार करे, उसका विरोध करो', चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मज़ाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है। भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की ज़रूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धीरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा। भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। लेकिन जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह यह है कि इस पूरी कवायद के दौरान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर इसका विरोध करता नजर आया, भले ही मामला राष्ट्रहित और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हो। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने, फर्जी वोटरों की छंटनी, और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक शुद्धिकरण था। यह सुधार न केवल चुनावों को पारदर्शी बनाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। परन्तु कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और इसे जातीय आंकड़ों, राजनीतिक संतुलन और चुनावी गणित से जोड़कर कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण संविधान सम्मत प्रक्रिया है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को न केवल वैध बताया, बल्कि उसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी बताया। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अब समय आ गया है जब चुनावी ईमानदारी को राजनीतिक शोरगुल और वोट बैंक की राजनीति के शोर में दबाया नहीं जा सकता। विपक्ष की प्रतिक्रिया लगभग स्वचालित होती जा रही है, चाहे मुद्दा हो आर्थिक सुधार का, रक्षा नीति का, विदेश नीति का, या अब मतदाता सूची सुधार का। प्रश्न यह उठता है कि क्या हर सुधार प्रक्रिया, चाहे वह कितनी भी लोकतांत्रिक या पारदर्शी हो, विपक्ष के लिए मात्र एक राजनैतिक खतरा है? विपक्ष का यह रवैया यह दर्शाता है कि उसे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम और अपनी राजनीतिक गणनाओं पर भरोसा अधिक है। एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना। यदि कोई सुधार प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि एक भी फर्जी वोटर सूची में न हो, कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची बने, तो फिर उसका विरोध क्यों?विपक्ष इस डर से ग्रस्त है कि यदि मतदाता सूची साफ-सुथरी हो गई, तो उनके कथित परंपरागत वोट बैंक कमजोर हो सकते हैं। उन्हें डर है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन यह तर्क लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है।

अजब-गजब

कभी होटल में बर्तन मांझती थी 20 साल की ये लड़की, अब हर साल महीने कमाती है 30 करोड़ रुपये!

अमेरिका के फ्लोरिडा की रहने वाली 20 वर्षीय सोफी रैन इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हो भी क्यों नहीं, आखिर इस लड़की की कहानी ही कुछ ऐसी है। सोफी कभी होटल में बर्तन मांजती थीं, लेकिन इंटरनेट की 'दुनिया' में धमाल मचाकर हर महीने 3.16 मिलियन डॉलर (यानी लगभग 30 करोड़ रुपये) कमा रही हैं। आइए जानते हैं इस लड़की की गरीबी से अरबपति बनने का सफर के बारे में।

सोफी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। मियामी की सोफी बताती हैं कि उनके परिवार को गुजारा करने के लिए अक्सर फूड स्टैम्प्स (अमेरिका में कम आय वाले परिवारों को मिलने वाले फूड बेनिफिट्स और वित्तीय मदद) पर निर्भर रहना पड़ता था। अपने माता-पिता की आर्थिक तंगी देखकर उनका दिल टूट जाता था। 17 की उम्र में उन्होंने एक होटल में वेट्रेस का काम शुरू किया, लेकिन उनकी खूबसूरती और सोशल मीडिया पर बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया।

उनकी किस्मत तब पलटी जब उन्होंने दोस्तों के कहने पर एडल्ट साइट ओनलीफैन्स जॉइन किया। फिर देखते ही देखते सोफी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 70 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए, और अब वह ओनलीफैन्स की नंबर वन स्टार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोफी ने सिर्फ एक साल में ही 43 मिलियन डॉलर (यानी लगभग 360 करोड़ रुपये) की कमाई की है। इस हिसाब से देखा जाए, तो उन्होंने हर महीने 30 करोड़ कमाए।

जाहिर है, अधिकांश लोगों की नजरों में सोफी का प्रोफेशन सही नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि उनकी नीयत साफ है और भगवान उनकी मजबूरी समझते हैं। उन्होंने कहा, हफ्ते के छह दिन मैं अपने पुरुष फैन्स से ऑनलाइन चैट करती हूं, और सातवें दिन चर्च जाकर भगवान से माफी मांगती हूं। उनका का कहना है कि जब तक भगवान कोई 'संकेत' नहीं देते, वो ये काम नहीं छोड़ेंगी। सोफी ने कहा, मैं वर्जिन हूं, और शादी तक इसे बनाए रखना चाहती हूं। उन्हें हर दिन शादी के प्रपोजल और मोटी रकम के ऑफर आते हैं, पर वह अपने सिद्धांतों पर अड़ी हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैं सिर्फ सच्चा प्यार चाहती हूं।

फिलहाल, सोफी की इस अजब-गजब कहानी ने इंटरनेट पर खूब हंगामा मचाया हुआ है। कुछ लोग उनकी हिम्मत और अपने परिवार के प्रति समर्पण की तारीफ कर रहे हैं, कई लोगों ने उनके प्रोफेशन को धार्मिक और नैतिक रूप से गलत बताया है।

ब्लॉग

UP में विद्यालय विलय नीति का विरोध करने वाले बच्चों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को आपस में मर्ज (विलय) करने का फैसला किया तो इस पर राजनीति और हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी नेता इस नीति को छात्रों के विरोध में बताते हुए बयानबाजी करने लगे, शिक्षकों की ओर से भी इस नीति का विरोध जताया जाने लगा, अभिभावक भी चिंतित होने लगे, कोई इस नीति के विरोध में कोर्ट चला गया तो कोई सोशल मीडिया पर इसके विरोध में तमाम पोस्टें किये जा रहा है। लेकिन आप इस नीति का विरोध कर रहे लोगों की बातों को सुनेंगे या उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ेंगे तो एक बात साफ हो जायेगी कि इन्हें शिक्षा में सुधार से कोई लेना-देना नहीं है। किसी को अपनी राजनीति चमकानी है तो किसी को अपने लिये बरसों से बने सुविधाजनक माहौल से बाहर नहीं निकलना है।

जबकि असल में देखा जाये तो योगी सरकार की स्कूलों को मर्ज करने की नीति केवल प्रशासनिक सुधार भर नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से एक दूरदर्शी कदम है। इस नीति के दूरगामी प्रभाव छात्रों और उनके अभिभावकों के हित में साबित होंगे। हम आपको बता दें कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को पास के ज्यादा छात्रों वाले विद्यालयों में समायोजित कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज किया जाना इस नीति की वैधता का प्रमाण भी है।

स्कूलों को मर्ज करने की नीति का विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि छोटे-छोटे विद्यालयों में अक्सर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिलती है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, स्मार्ट क्लास, साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी चीजों का भी अभाव होता है। जब दो या तीन स्कूलों को मर्ज कर एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा, तो संसाधनों का केन्द्रीयकरण होगा। इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल, अच्छी बिल्डिंग, खेल-कूद और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इसके अलावा, अभी कई स्कूलों में एक या दो अध्यापक ही पूरे विद्यालय का भार उठा रहे हैं। इससे न तो शिक्षक विषय विशेषज्ञ बन पाते हैं और न ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। मर्ज किए गए बड़े स्कूलों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार के लिए आसान होगा। इससे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में भी बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सकेगा।

साथ ही मर्जिंग के बाद स्कूलों में केवल छात्र संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि प्रतियोगिता, नवाचार और गतिविधियों के अवसर भी बढ़ेंगे। बड़े स्कूलों में सामान्यतः बेहतर शैक्षणिक माहौल होता है, जिससे बच्चों के सीखने का स्तर स्वतः ही ऊपर उठता है। इससे बच्चों की नींव मजबूत होगी और आगे चलकर वे प्रतियोगी परीक्षाओं व कॅरियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

इसके अलावा, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने को मजबूर होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षा स्तर कमज़ोर होता है। लेकिन जब सरकारी स्कूल ही बेहतर आधारभूत सुविधाओं और योग्य शिक्षकों से सुसज्जित होंगे, तो अभिभावकों का भरोसा इन स्कूलों पर बढ़ेगा। इससे शिक्षा पर उनका अतिरिक्त आर्थिक भार भी घटेगा।

इसके अलावा, कम स्कूलों का प्रबंधन करना सरकार और शिक्षा विभाग दोनों के लिए आसान होगा। निरीक्षण, ऑडिट और सुधारात्मक कदम जल्दी और प्रभावी ढंग से लिए जा सकेंगे। इससे विद्यालयों में जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार या लापरवाही पर भी अंकुश लगेगा।

वहीं स्कूलों की मर्जर पॉलिसी को लेकर उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों और शिक्षकों के बीच जो भ्रम और विरोध की स्थिति देखी जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें इस नीति के उद्देश्यों से भलीभांति अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए विशेषकर वे शिक्षक, जिनका स्थानांतरण (ट्रांसफर) दूर-दराज़ क्षेत्रों में होने की आशंका है, इस नीति को अपने भविष्य के लिए खतरा मानकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि वे इस नीति के दीर्घकालिक लाभों और शिक्षा व्यवस्था में इसके सकारात्मक प्रभाव को समझेंगे तो वह स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह परिवर्तन उनके लिए नुकसान नहीं, बल्कि अवसरों के नए द्वार खोलने वाला है।

बहुत से शिक्षक सोच रहे हैं कि स्कूलों के मर्जर से उनके वर्तमान स्कूल बंद हो जाएंगे और उन्हें दूर के विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वह यह मानते हैं कि इससे उन्हें पारिवारिक, सामाजिक और दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले शिक्षकों को अपना विरोध छोड़ देना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आज जिन छोटे स्कूलों में वह काम कर रहे हैं, वहाँ न तो पर्याप्त छात्र हैं और न ही आधारभूत सुविधाएँ। स्कूलों के मर्जर के बाद बड़े, बेहतर संसाधनयुक्त विद्यालयों में तैनाती मिलने से काम करने का वातावरण सुधरेगा। साफ-सुथरी बिल्डिंग, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और डिजिटल क्लास जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, जहाँ बच्चे अधिक होंगे, वहाँ शिक्षकों की जिम्मेदारी के साथ-साथ उनके अनुभव और दक्षता में भी वृद्धि होगी। ऐसे विद्यालयों में कार्य करते हुए शिक्षक नवाचार, प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग जैसी योजनाओं से सीधे जुड़ेंगे। इससे उनके कॅरियर में प्रगति के द्वार खुलेंगे।

शिक्षकों को यह भी समझना चाहिए कि स्थानांतरण कोई दंड नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के संतुलन का माध्यम है। जिन शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा, उन्हें भी बेहतर सुविधा वाले विद्यालयों में ही भेजा जाएगा। लंबे समय में यह व्यवस्था स्थिर होगी और अराजकता कम होगी।

देखा जाये तो एक शिक्षक का प्रथम कर्तव्य बच्चों के भविष्य को संवारना है। स्कूल मर्जर से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, उनका ड्रॉपआउट रेट घटेगा और वे प्रतिस्पर्धी भविष्य के लिए तैयार होंगे। जब शिक्षा बेहतर होगी, तो शिक्षक का सम्मान भी स्वतः बढ़ेगा। इसके अलावा, छोटे-छोटे विद्यालयों में बिखरी शिक्षक शक्ति को एक जगह लाकर सामूहिक रूप से मजबूत किया जाएगा। इससे शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा और शिक्षकों की भूमिका ज्यादा प्रभावशाली बनेगी।

देखा जाये तो विद्यालय विलय नीति से डरने या उसका विरोध करने का कोई तर्क नहीं है। बदलाव के हर कदम में प्रारंभिक कठिनाई होती है, लेकिन दूरदर्शिता रखने वाले शिक्षक समझते हैं कि यह नीति बच्चों के भविष्य, शिक्षकों की गरिमा और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे डर या भ्रम छोड़कर इस नीति का स्वागत करें और इसे अपने सुनहरे भविष्य के अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक सोच के साथ परिवर्तन को अपनाना ही चाहिए क्योंकि यही भविष्य का आधार होता है।

अब जरा बात उन अभिभावकों की कर ली जाये जो अपने बच्चे के स्कूल के दूर हो जाने की चिंता से ग्रस्त हैं। देखा जाये तो अभिभावकों के मन में यह चिंता उठना स्वाभाविक ही है कि अब उनके बच्चे का स्कूल पहले से कुछ दूर हो जाएगा। ऐसे अभिभावक सोच रहे हैं कि बच्चों को रोज़ाना ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे परेशानी बढ़ेगी। लेकिन वक्त की आवश्यकता यह है कि अभिभावकों को दूरी की चिंता छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल आज के समय में यह देखना अधिक ज़रूरी है कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ उसे कैसी शिक्षा, कैसी सुविधाएं और कैसे अवसर मिल रहे हैं। यदि स्कूल थोड़ा दूर है लेकिन वहाँ अच्छे शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, डिजिटल शिक्षा, खेलकूद और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के अवसर मिल रहे हैं तो यह दूरी बच्चों के भविष्य के सामने बिल्कुल छोटी बात है।

इसके अलावा, निकट का स्कूल अगर सुविधाविहीन, अध्यापकविहीन और कमजोर है, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षणिक विकास बाधित होगा। जबकि कुछ किलोमीटर दूर का स्कूल अगर बच्चों को आधुनिक शिक्षा, अनुशासन और अवसर दे रहा है, तो वही बच्चा आगे चलकर आत्मनिर्भर और सफल बन पाएगा।

देखा जाये तो हर गाँव में छोटा-छोटा स्कूल खोल देने से शिक्षा मजबूत नहीं होती। एक ऐसा स्कूल जहाँ योग्य शिक्षक, बेहतर पढ़ाई, खेल का मैदान, आधुनिक लैब और स्मार्ट क्लास हो, बच्चों के विकास के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ बच्चे प्रतिस्पर्धा सीखेंगे, दोस्त बनाएंगे और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ेंगे। अभिभावकों को यह पता होना चाहिए कि ऐसी तमाम देशी-विदेशी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि भारत में बच्चों की शिक्षण गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अभिभावकों को समझना होगा कि स्कूल की दूरी बढ़ना असली चुनौती नहीं है, असली चुनौती है अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना।

अभिभावकों को समझना होगा कि आज भले ही बच्चा स्कूल जाने के लिए 2-3 किलोमीटर ज़्यादा चले, लेकिन जब वह अच्छे स्कूल में पढ़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा, तो उसी माता-पिता को गर्व होगा कि उन्होंने अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए यह छोटा सा समझौता किया। अभिभावकों को समझना होगा कि आपका फर्ज सिर्फ यह नहीं कि बच्चा घर के नजदीक स्कूल में पढ़े। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उसे ऐसा माहौल दें, जहाँ वह अच्छे शिक्षक, संसाधन और अवसर पाकर अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसलिए स्कूल पास हो या दूर, अगर वहाँ पढ़ाई बेहतर है, तो वही सही विकल्प है।

दूरी की नहीं, गुणवत्ता की चिंता करें। भविष्य तभी बदलेगा, जब शिक्षा मजबूत होगी। सबको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के विलय से शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। बच्चों को वह सब मिलेगा, जो अभी बड़े शहरों के स्कूलों में मिलता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को प्राथमिकता दें, न कि केवल दूरी को। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा का हर कदम भविष्य तक जाता है— चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों न हो।₹

बहरहाल, देखा जाये तो विद्यालयों के विलय की यह नीति केवल ढांचागत सुधार नहीं है, बल्कि शिक्षा के स्तर को सुधारने, बच्चों के भविष्य को

बीजेपी महिला नेता के पति की दबंगई... बीच सड़क युवक को लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीजेपी नेता के पति की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां बीजेपी की ब्लॉक प्रमुख संजना सैनी के पति ने अपने ड्राइवर और एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक युवक की बीच सड़क पर लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित युवक नाम चिंटू है। इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना जिले के कोतवाली ठाकुरद्वारा इलाके की है।

इसने स्थानीय स्तर पर सनसनी मचा दी है। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख संजना सैनी के पति का नाम वीर सिंह सैनी है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक पिटाई से बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वीर सिंह सैनी और उसके साथियों ने उसे दौड़ाकर पीटा। इस दौरान

आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। कोई भी पीड़ित युवक की सहायता के लिए आगे नहीं आया।

राजनीतिक गलियारों में मची खलबली

किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी। घटना के बाद वीर सिंह सैनी स्वयं थाने पहुंचा और चिंटू पर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और चाकू से हमला कर घायल करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर, पीड़ित चिंटू का दावा है कि उसकी पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उसने वीर सिंह सैनी की गुंडागर्दी का विरोध किया था। चिंटू का कहना है कि यह पिटाई बदले की भावना से की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण करवाया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। चूंकि यह घटना एक बीजेपी नेता से जुड़ी है, इसलिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्ता के दम पर ऐसे दबंगों को खुली छूट दी जा रही है, जिसके कारण आम जनता डर और असुरक्षा के माहौल में जी रही है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना में पीड़ित चिंटू ने कहा "मैंने केवल उनकी गुंडागर्दी का विरोध किया था। इसके बाद वीर सिंह सैनी और उसके साथियों ने मुझे दौड़ाकर लाठी-डंडों से मारा। मैं बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले।" वीर सिंह सैनी ने कहा कि चिंटू ने मेरे साथ 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। मुझे चाकू मारकर घायल किया था। यह उसी का जवाब था। मैंने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी।

कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही घटना

यह घटना मुरादाबाद में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों में गुस्सा पैदा किया है। कई लोग इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण मान रहे हैं। पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर निष्पक्ष जांच का वादा किया है, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या वाकई में इस घटना में न्याय मिलेगा। इस घटना ने सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। घटना को लेकर एसपी देहात मुरादाबाद कुंवर आकाश सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले में जांच के आदेश दिया है और जानकारी दी है।

कानपुर का नया सीएमओ कौन? हरिदत्त नेमी का सस्पेंशन रद्द, उदयनाथ को वापस भेजा श्रावस्ती

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दिनों चले सीएमओ मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। शासन ने कानपुर के सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को हटाकर वापस श्रावस्ती भेज दिया गया है। वहीं पूर्व सीएमओ डॉ हरिदत्त का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है। अब नया सवाल खड़ा हो गया है कि कानपुर का सीएमओ कौन है? कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी की कई शिकायतें मिलने के बाद डीएम ने उनको हटाने की संस्तुति शासन से कर दी थी।

पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के ऊपर मनमाने ट्रांसफर, आदेशों का पालन न करना, अधीनस्थों पर पकड़ न होना समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद शासन ने डॉ हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया और कानपुर का नया सीएमओ श्रावस्ती से डॉक्टर उदयनाथ को बना दिया। शासन के आदेश के खिलाफ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी के सस्पेंशन पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं डॉक्टर उदयनाथ के कानपुर ट्रांसफर ऑर्डर पर भी रोक लगा दी।

दोनों ने किया था अपना दावा

इस ऑर्डर के होने के बाद बुधवार को डॉक्टर हरिदत्त नेमी कानपुर पहुंचे और सीएमओ की सीट पर बैठकर अपने आप को सीएमओ घोषित कर दिया। इसकी जानकारी जब डॉक्टर उदयनाथ को हुई तो वो भी ऑफिस पहुंच गए और दोनों सीएमओ एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ का कहना था कि हाइकोर्ट के आदेशों का सभी को पालन करना होता है। लेकिन डॉक्टर हरिदत्त नेमी को यह आदेश शासन में देकर प्रोसेस के तहत आना चाहिए था। वह सीधे यहां आकर सीएमओ नहीं बन सकते। डॉक्टर उदयनाथ ने खुद के सीएमओ होने का दावा किया है।

अब कौन है कानपुर का नया सीएमओ ?

इसके बाद शासन की तरफ से वर्बल ऑर्डर आया और हरिदत्त नेमी को कुर्सी से हटाकर डॉ उदयनाथ को काबिज किया गया। अब शासन ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत डॉक्टर उदयनाथ को वापस श्रावस्ती भेज दिया गया है। इसके साथ ही दूसरा ऑर्डर भी किया गया है, जिसके तहत डॉक्टर हरिदत्त नेमी का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिकार आज की तारीख में कानपुर का सीएमओ कौन है? या फिर यह माना जाए कि कानपुर के सीएमओ की सीट खाली है।

भारतीय किसान यूनियन कार्यालय का हुआ उद्घाटन

आर्यावर्त संवाददाता

मोहम्मदी-खीरी। जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत मोहम्मदी क्षेत्र के पिपरिया धनी में भारतीय किसान यूनियन कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बापू अजीत सिंह जी ने फीता काटकर किया गया जिससे किसानों को अपनी समस्या को किसान नेताओं को आगमन करने में आसानी होगी जिससे क्षेत्र के किस आराम से पहुंच कर अपनी समस्या से भागवत कर सकेंगे कार्यालय का उद्घाटन बहुत ही भव्य तरीके से किया गया जिसे किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखें और कई समस्याओं का समाधान भी हुआ शुभारंभ के दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह जी, युवा जिलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू यादव जी, बलवीर सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव डॉक्टर शाजी अल्वी जी, मोहम्मद आरिफ सुल्तान युवा जिला सचिव जी, गुरजीत सिंह जी, टीटू भैया जी, साहब सिंह जी, रणधीर सिंह जी युवा जिला महासचिव, सुखदेव सिंह जी, मोहम्मद इलियास, नन्हे शाह, सहित तमाम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों सहित आदि क्षत्रिय किसान मौजूद रहे 1

'पीटता था, सिगरेट से दागता था... 6 साल से नहीं लौटी मेरी बहन', छांगुर के दोस्त अख्तर पर घिनौने आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इन दिनों चर्चा में है। पुलिस ने उसे धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब गाजियाबाद की एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी बहन को 2019 में बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के एक शख्स ने गायब कर दिया, जो छांगुर बाबा का खास आदमी है। लापता युवती की बहन का दावा है कि उसकी बहन टूर एंड ट्रेवल्स का कोर्स कर रही थी। तभी उसकी जान-पहचान बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के शख्स से हुई।

इसके बाद वो उसे गाड़ियों में घुमाने, बातें करने और फिर धीरे-धीरे मानसिक रूप से काबू में लेने लगा। 24 अक्टूबर 2019 को बदर अख्तर उसे अपने साथ ले गया और फिर युवती कभी घर नहीं लौटी। लापता युवती के बहन का आरोप है कि बदर अख्तर के संपर्क में आने के बाद

उसकी बहन का बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। वो पूजा-पाठ से दूर हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी और सिर्फ बदर अख्तर की बातें करती थी।

बहन ने ब्रेनवॉश करने का लगाया आरोप

बहन का दावा है कि उसका बुरी तरह ब्रेनवॉश कर दिया गया था। बदर अख्तर उसकी बहन को छांगुर बाबा का पढ़ा हुआ पानी और चावल खिलाया करता था। लापता युवती की बहन का आरोप है कि बदर अख्तर युवती के साथ मारपीट करता था। उसे सिगरेट से जलाता था और बीमार पड़ने पर छांगुर बाबा का पानी पिलाता था। बदर छांगुर बाबा का खास आदमी है।

अख्तर को गिरफ्तार करने की मांग की

युवती की बहन का दावा है कि जब उन्होंने अपनी बहन की खुद जानकारी जुटाई तो पाया कि सिर्फ उसकी बहन ही नहीं, बल्कि कई लड़कियां बदर अख्तर के संपर्क में आने के बाद गायब हो चुकी हैं। अब लापता युवती की बहन ने सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराई जाए और बदर अख्तर सिद्दीकी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि जब तक ये गिरफ्त में नहीं आएगा। तब तक न जाने कितनी लड़कियों की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी।

कौन है जमालुद्दीन छांगुर बाबा?

बलरामपुर के रेहरा माफी गांव के रहने वाले जलालुद्दीन को छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है। वह पहले रत्नों और अंगूठियों का छोटा-मोटा कारोबार करता था। इसके बाद जमालुद्दीन धीरे-धीरे एक धार्मिक गुरु बन गया और उसने ग्रामीण हिंदू आबादी का विश्वास जीता। लेकिन जांच में सामने आया कि उसने कोडवर्ड्स जैसे प्रोजेक्ट (हिंदू महिलाओं के लिए) और मिट्टी पलटना (धर्मांतरण के लिए) का इस्तेमाल कर अपने अवैध कारनामों को अंजाम दिया। उसका नेटवर्क काफी बड़ा है, जो नेपाल की सीमाओं तक फैला हुआ है। लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो गया है।

'रुक, एक-एक पुलिसवाले को 500-500 का नोट दे...', मना किया तो 11 पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर की फोड़ दी आंख, हुआ ये एक्शन

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पशु व्यापारी से वसूली करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। आलाधिकारियों ने वसूली के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी है। आलाधिकारियों के इस कदम से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चार दिन पहले रात को मोहम्मद उजैर नाम का व्यापारी अपने पिकअप से भौति हाइवे से जा रहा था। पिकअप को लकी नाम का ड्राइवर चला रहा था। आरोप है कि उसी समय रात को तीन पीआरवी में मौजूद 11 पुलिसकर्मियों ने पिकअप को रोका और 500 रुपए प्रति व्यक्ति वसूली की मांग की। इतने पैसे न होने की बात कहने पर पुलिस वालों ने लकी को डंडे से मार जिसकी वजह से उसकी आंख में चोट भी लग गई।

जब इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की तो आलाधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की। जांच में प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मी दोषी पाए गए जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ित का कहना था कि यह लोग हर बार उससे 200 रुपए प्रति व्यक्ति वसूलते थे। वह पैसे जमीन पर फेंक कर चला जाता था और यह लोग उठा लेते थे। उस दिन इन्होंने 500 रुपये प्रति व्यक्ति की डिमांड की जिसको देने में असमर्थता जताई जिसके बाद उन्होंने डंडे से मारा-पीटा। यही नहीं, ड्राइवर की आंख तक फोड़ दी। पुलिस वालों ने गाड़ी रोककर कहा- रुक, हम 11 लोग हैं। 500-500 के 11 नोट दे। बसी यहीं से विवाद शुरू हुआ।

लगातार लग रहे पुलिसकर्मियों पर आरोप

इस पूरे मामले में डीसीपी क्राइम आबिद कासमी का कहना है कि जांच में पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है और साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्ता की जांच भी हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक साथ इतने पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी पुलिसकर्मी समझौते की कोशिश में भी लगे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में पुलिस कर्मियों पर लगातार आरोप लग रहे है जिसके बाद विभाग की छवि दागदार हो रही है।

विधायक ने किया अंतेष्टि स्थल का शिलान्यास

गोण्डा। जनपद के विकासखंड बेलसर के ग्राम पंचायत डिडिसिया कला में अंतेष्टि स्थल निर्माण कार्य का तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय ने बैदिक मन्त्रोंचार एवं हवन पूजन के साथ विधि विधान से शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय ने कहा कि तरबगंज विधानसभा में हर तरफ विकास कार्य दिखाई दे रहा है। बिजली व्यवस्था में सुधार हो रहा हैं। यह श्रेय हमारे योगी जी मोदी जी को जाता है। हमारी सरकार ने लोगों के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। मैं आप लोगों एवं क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हूं। प्रधान प्रतिनिधि शुभम उपाध्याय ने कार्यक्रम में आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य विनोद पांडेय, जिला पंचायत सदस्य रवींद्र पांडेय, प्रधान प्रतिनिधि शुभम उपाध्याय राजेंद्र प्रसाद तिवारी, समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

नोएडा की इन 50 सोसायटियों पर चलेगा बुलडोजर, 39 डेवलपर्स को मिला नोटिस

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से अधिक अवैध आवासीय सोसायटियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। 39 डेवलपर्स को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में निर्माण हटाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। ये कॉलोनियां महर्षि आश्रम की जमीन पर बसाई जा रही हैं जहां 2018 से अवैध निर्माण चल रहा है।

सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर डेवलपर्स द्वारा अतिक्रमण कर बसा जा रही 50 से अधिक आवासीय सोसायटी को प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। सीईओ लोकेश एम ने अधीनस्थों से इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीईओ सख्ती के बाद प्राधिकरण

अधिकारियों ने इन्हें अवैध घोषित कर बड़ी कार्रवाई की। निर्माण साइट पर नोटिस चस्पा करने के लिए वर्क वर्क सर्किल आठ वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी व भूलेख विभाग डिप्टी कलेक्टर शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ टीम पहुंची।

39 डेवलपर की निर्माणाधीन साइट पर काम रुकवाया, उन्हें नामजद कर बिल्डिंगों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया, जिसमें लिखा कि एक सप्ताह में अवैध निर्माण खुद ध्वस्त कर प्रत्यावेदन कार्यालय में जमा करे अन्यथा अवैध निर्माण को प्राधिकरण सील कर ध्वस्त कराएगा। इस दौरान कार्रवाई के विरोध में एकत्र डेवलपर्स ने करीब तीन घंटे तक निर्माणाधीन साइट पर हाइ वोल्टेज ड्रामा किया, लेकिन मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली।

बिना स्वीकृति के निर्माण हो रहा

अधिकारियों ने बताया जिन खसरा नंबर पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, तमाम खसरा नंबर की जांच जिला प्रशासन कर रहा, क्योंकि खसरा की जमीन को गलत तरीके से किसानों ने अपने नाम दाखिल खारिज कराया है। अन्य खसरा नंबर महर्षि आश्रम की जमीन है, जिस पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना व मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण हो रहा है।

आम जनमानस से अपील की गई है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित व अर्जित भूमि है, जिनका खसरा संख्या 723, 724 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 पर अवैध निर्माण है। इस भूमि पर किसी प्रकार की खरीद फरोख्त न की जाए, वित्तीय हानि हो सकती है।

जामुन खिलाने के बहाने मासूम बच्ची घर ले गया पड़ोसी युवक... फिर कर डाली हैवानियत

आर्यावर्त संवाददाता

इटावा। इटावा जिले के बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की शाम 22 वर्षीय युवक ने जामुन खिलने के बहाने घर में ले जाकर एक छह साल मासूम बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची को देर रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक, बसरेहर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुए रेप कि जानकारी तब हुई, जब पीड़ित बच्ची के परिवार के लड़के ने पड़ोसी को उसको घर ले जाते देखा। इसकी शिकायत बच्चे ने पीड़ित बच्ची की मां से की। फिर पीड़िता की मां ने बड़ी बेटी को भेजा तब उसने देखा कि आरोपी उसकी बहन के साथ घर के अंदर गलत काम

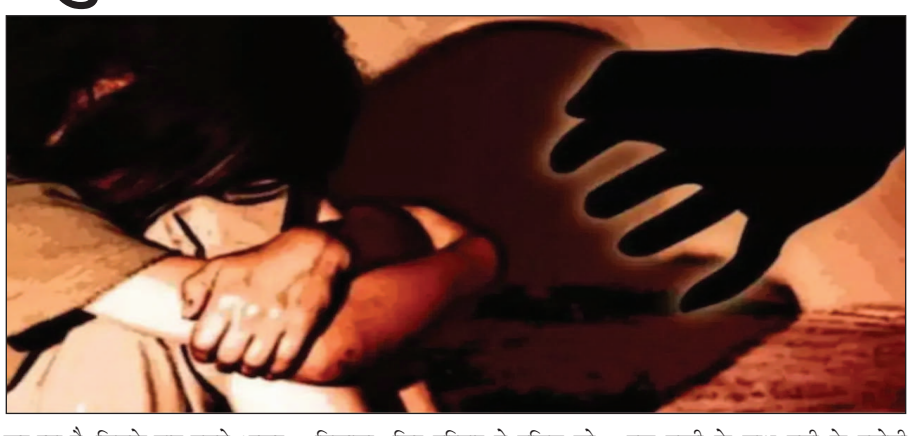

कर रहा है, जिसके बाद उसने आकर अपनी मां को बताया।

घटना की जांच पड़ताल की गई

इसके बाद पीड़ित की मां और परिवार के लोगों ने आरोपी के घर पहुंचकर मासूम बच्ची को बाहर निकाला। फिर परिवार ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर फॉरेंसिक टीम, एसपी ग्रामीण, सीओ सैफई पहुंचे। घटना की जांच पड़ताल की गई और आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

इस पूरी घटना के बारे में सीओ सैफई रामगोपाल शर्मा ने बताया कि एक बच्ची के साथ उसी के पड़ोसी युवक के द्वारा रेप का मामला संज्ञान में आया था। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पीड़ित की मां ने क्या बताया?

वहीं पीड़िता की मां ने जानकारी देते हुए बताया है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक जोकि घर में अकेला रहता है। मेरी बच्ची जब शाम को जामुन तोड़ने गई थी, तब वो उसे जामुन का लालच देकर अपने खाली मकान में ले गया। मेरे परिवार के एक बच्चे ने मुझे सूचना दी, कि पड़ोस का रहने वाला युवक छोटी बिटिया को पकड़े हुए है। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को भेजा। बड़ी बेटी ने देखा कि युवक उसकी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा है। फिर वो भागकर मेरे पास आई। इसके बाद हम पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। मैं चाहती हूं कि आरोपी को कम से कम आजीवन कारावास हो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते।

बिना रजिस्ट्रेशन क्लीनिकों पर चला स्वास्थ्य विभाग का चाबुक

» जाँच टीम आते ही कई क्लिनिक बंद कर भाग गए संचालक

आर्यावर्त संवाददाता

मैगलगंज-खीरी। औरंगाबाद मे तमाम अबैध रूप से संचालित क्लिनिको कि खबरें लगातार औरंगाबाद को सुर्खियों मे बनाये हुए थी जिसके बाद बुधवार को स्वास्थ्य महकमा कि नींद टूटी, सुफियान क्लिनिक व रवि हेल्थ केयर पर जाँच कर थमाई नोटिस, व तत्काल प्रभाव से संचालन भी रुकबाया गया। साथ ही बीते सप्ताह बुधवार को औरंगाबाद कस्बा रोड पर संचालित डॉ. अंकुर गुप्ता के क्लिनिक पर जाँच कर कि कार्यवाही, साथ ही पूर्व मे 13 वर्षीय बच्ची कि मौत का तीन दिन मे स्पष्टीकरण माँगा गया बता दे यह

कार्यवाही नोडल अधिकारी डॉ. निशांत गुप्ता द्वारा कि गयी है। औरंगाबाद के अबैध हॉस्पिटल व क्लिनिक लगभग पिछले एक सप्ताह से लगातार अखाबारी सुर्खिया बटोर रहे थे, जिसका एक सप्ताह के बाद संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस देकर तत्काल प्रभाव से संचालन रोकने कि कार्यवाही कि गयी।

क्या बोले जिम्मेदार

औरंगाबाद मे कई जगह जाँच कि है जिसमे पिछले सप्ताह हुई बच्ची कि मौत को लेकर अंकुर गुप्ता से स्पष्टीकरण माँगा गया है, जो उच्च अधिकारियो को प्रेषित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सुफियान क्लिनिक व रवि हेल्थ केयर को नोटिस देकर तत्काल प्रभाव से संचालन रुकबा दिया गया है।

कैटरीना कैफ की तरह रहेंगी फिट, 40 के पार जाते ही रोजाना करें ये 4 योगासन

कैटरीना कैफ आज अपना 42वां जन्मदिन मना रही हैं। 40 की उम्र के बाद भी एक्ट्रेस काफी फिट हैं। अगर आप भी 40 की उम्र पार कर चुकी हैं और फिट रहना चाहती हैं तो हम आपके लिए 4 ऐसे योगासन लाए हैं, जो 40 के बाद भी आपको रखेंगे फिट और हेल्दी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपने टोन्ड फिगर और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। कैटरीना आज यानी 16 जुलाई को अपना 42वां जन्मदिन मनाया। कैटरीना अपनी फिटनेस से अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं। अगर आप भी 40 पार चुकी हैं और कैटरीना की तरह फिट दिखना चाहती हैं तो हम आपको ऐसे 4 योगासन बताएंगे, जिसे रोजाना करके आप भी जवां दिख पाएंगी।

फिट रहने के लिए योग करना एक शानदार तरीका है। खासकर जब आप 40 पार कर लेती हैं तो तनाव और चिंता के कारण कई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप रोजाना योग करेंगी तो आपके शरीर को मजबूती मिलेगी। योग करने से रात को अच्छी नींद भी आएगी। यह स्वस्थ्य रहने ले लिए बहुत जरूरी है। बढ़ती उम्र को आप योगा के जरिए एक नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और फिगर भी शेप में आ जाएगा। जानिए ऐसे 4 योगासन जो 40 की उम्र में भी 25 साल वाला एहसास करवाएंगे।

भुजंगासन करें तनाव कम

इस आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। जो भी महिलाएं कमर में दर्द, गर्दन में दर्द या बढ़ती उम्र में वजन बढ़ने से परेशान रहती हैं, उन्हें ये आसन जरूर करना चाहिए। इसे करने से बीमारियां दूर होंगी और वजन भी घटेगा। ये आसान आपके किडनी,लिवर और फेफड़ों को भी स्वस्थ बनाता है।

सेतुबंधासन करें और पेट की बीमारियों को कहें अलविदा

पहले इसका मतलब समझें, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सेतु और बांध का मतलब होता है पुल। इसलिए इसे अंग्रेजी में ब्रिज पोज भी कहते हैं। अगर आप रोजाना इस आसन को करेंगे तो आपको पेट की बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी।इसके अलावा इसके बहुत फायदे हैं। जैसे कि मासिक धर्म के दर्द से राहत और ये आपके फेफड़ों को भी खोलता है।

पाचन सुधारेगा पश्चिमोत्तानासन आसन

इस आसन को अंग्रेजी में सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। पाचन को सुधारने के अलावा ये आसम आपके पैरों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। 40 पार करने के बाद ज्यादातर महिलाओं को पीठ और पैरों में दर्द की शिकायत रहती है।रोजाना नियमित तौर पर इस आसन को करने से उन्हें इससे भी मुक्ति मिलेगी।

रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएगा अधोमुख श्वानासन

इस आसन को अंग्रेजी में डाउनवर्ड-फेसिंग डॉग कहते हैं। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस आसन में कुत्ते की तरह बॉडी शेप होती है। ये आसन आपके स्ट्रेस को दूर करेगा साथ ही इससे आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी। इसे नियमित तौर पर करने से आपकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप मिलेगा। ध्यान रखें, योगा के साथ-साथ एक अच्छी डाइट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पोषण से भरपूर डाइट लेंगे तो योगा करने का लाभ बढ़ जाएगा।

कैटरीना कैफ की ये वर्कआउट टेक्निक बना सकती है आपको भी टोन्ड और स्ट्रॉन्ग

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि फिटनेस को लेकर भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। उनकी टोन्ड बॉडी, फ्लैट एब्स और स्ट्रॉन्ग फिजिक को देखकर हर कोई यही सोचता है कि वो घंटों जिम में वेट लिफ्टिंग करती होंगी। हालांकि, कैटरीना एक ऐसी एक्सरसाइज टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिसने उन्हें एक टोन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉडी देने में हेल्प की है।

कैटरीना अपनी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन के साथ मिलकर एक खास वर्कआउट कर रही हैं, जिसमें हर सेशन में एक खास बॉडी पार्ट पर फोकस किया जाता है। ये एक्सरसाइज न सिर्फ बॉडी को टोन करती है बल्कि कोर स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बेहतर बनाती है। यही वजह है कि अब फिटनेस के मामले में कैटरीना कैफ सिर्फ एक स्टाइल आइकन ही नहीं, बल्कि एक फिटनेस आइकन भी बन चुकी हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है वो एक्सराइज।

जिम में ये एक्सरसाइज करती हैं कैटरीना

कैटरीना कैफ ने कुछ महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो जिम में एक्सरसाइज करती नजर आ रही थीं। इस वीडियो में कैटरीना पिलेट्स करती दिख रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था कि, – " मैं आमतौर पर जिम को प्रायोरिटी देती हूं, लेकिन अब समझ में आया है कि पिलेट्स के जरिए भी मसल्स पर अच्छा काम किया जा सकता है। मेरे साथ यास्मीन पिलेट्स सेशन में एक बॉडी पार्ट पर फोकस करने में मदद कर रही हैं। "

क्या होती है पिलेट्स एक्सरसाइज?

पिलेट्स एक ऐसी एक्सरसाइट टेक्नीक है जिसमें शरीर की कोर मस्लस को मजबूत बनाने पर फोकस किया जाता है। जैसे पेट, कमर और पीठ के हिस्सा। इसे बॉडी का पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस सुधारने के लिए भी किया जाता है। पिलेट्स करते समय ब्रीथिंग मूवमेंट का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसकी खास बात ये है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने में ही मदद नहीं करती , बल्कि ये कमर दर्द , पोस्चर सुधारने और मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। पिलेट्स एक्सरसाइज कई तरह की होती हैं, जिसमें मैट पिलेट्स, रिफॉर्मर पिलेट्स, और क्लासिकल पिलेट्स। इसके अलावा, कंटेम्परारी पिलेट्स, क्लिनिकल पिलेट्स, और STOTT पिलेट्स शामिल हैं।

टोन बोडी के लिए करें ये पिलेट्स एक्सरसाइज

ब्रीदिंग- टोंड बॉडी पाने के लिए आप कुछ पिलेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें पहली है ब्रीदिंग... ये बॉडी को शांत कर कोर मसल्स को एक्टिव करने में हेल्प करती है। इसमें आपको लेट कर हाथों को अपने पेट पर रखना है। इसके बाद आंख बंदकरके सांस अंदर लें।

शोल्डर ब्रिज प्रिपरेशन- इसके बाद करें शोल्डर ब्रिज प्रिपरेशन जो आपके ग्लूट्स और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए आपको जमीन पर लेटकर घुटनों को मोड़ना है और अपनी जांघो के नीचे एक तकिया या बॉल रखें। इसके बाद सांस लें और छोड़ते हुए बॉल को हल्का दबाएं, पैर से जमीन को पुश करें और धीरे-धीरे कमर को ऊपर उठाएं। अब सांस लें और कुछ सेकंड इसी पोज में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए कमर को धीरे-धीरे जमीन पर वापस लाएं।

लेग लिफ्ट्स- ये एक्सर्साइज एब्स और जांघों को टोन करने के लिए होती है। इसके लिए मैट पर लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लें और पैरों को हिप्स की चौड़ाई पर रखें। गहरी सांस लें और छोड़ते हुए पेट को हल्का अंदर खींचें। अब धीरे-धीरे एक पैर को ऊपर उठाएं, फिर दूसरी सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी ऊपर लाएं। अब दोनों पैरों को इसी पोजिशन में रखें और सांस लें। फिर धीरे -धीरे सामन्य पोजिशन में आ दाएं।

पार्टनर के साथ अगस्त में इन जगहों पर जाएं घूमने, हर पल बन जाएगा खास

अगर आप अगस्त में अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन खूबसूरत जगह पर जा सकते हैं। यहां आपको भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की सुंदरता के बीच अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।

आज के समय में अपनों के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। अगस्त के महीने में कुछ जगहें बेहद खूबसूरत हैं। आप अपने पार्टनर के साथ इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह जगहें बहुत ही खूबसूरत और भीड़भाड़ से दूर हैं।

जब भी घूमने का नाम आता है, तो ज्यादा लोग हिमाचल और उत्तराखंड जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन आप अगर में इन जगहों पर भी जा सकते हैं। यहां पर आपको शांति से एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में

चेरापूंजी

मेघालय में घूमने के लिए चेरापूंजी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां पर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है, जिसे रबर के पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है। इसके अलावा नोहकलिकाई झरना यहां बहुत ही प्रसिद्ध है। मावसई गुफा यहां की एक आकर्षक जगह है। इसके अलावा आप यहां पर दावकी नदी, इको पार्क, मावसमाई फॉल्स, डेनथलेन झरना, वाकाबा फॉल्स और मावडाक डिम्पेप घाटी जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कोडईकनाल

तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। धुंध से ढकी सुंदर चट्टानें और झरने इस जगह को लोकप्रिय बनाते हैं। यहां आपको भीड़भाड़ से दूर अपने पार्टनर के साथ शांति से समय बिताने का मौका मिल सकता है। आप यहां पर कोडईकनाल झील, बेरिजन झील, कोकर वॉक, ब्रायंट पार्क और पिलर रॉक पर इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कूर्ग

कूर्ग को कोडागु के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन हैं। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता है कारण जाना जाता है। यहां पर आप दुबारे हाथी शिविर, मदिकेरी किला, पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य, मंडलपट्टी व्यू पॉइंट, इरुप्पू फॉल्स और हरंगी बांध घूमने जा सकते हैं।

अलेप्पी

केरल में अलेप्पी एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहां अपने बैकवाटर्स, हाउसबोट्स, और समुद्र तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां आपको हाउसबोट में रहने का मौका मिल सकता है। यहां पर आलप्पुझा बीच, वेम्बनाड झील, कृष्णापुरम पैलेस और मरारी बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर आप चेट्टीकुलंगरा भगवती मंदिर और मुल्लाकल राजराजेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं।

इगतपुरी

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित इगतपुरी एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। आप यहां भी घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। यह मुंबई से लगभग 150 किमी की दूरी पर है। यहां पर आपको ट्रैकिंग करने का मौका मिल सकता है। इगतपुरी में एक्सप्लोर करने के लिए त्रिंगलवाड़ी किला, भातसा नदी घाटी, विल्सन डैम, कलसुबाई शिखर, विहिगांव झरना और धानगरवाड़ी झरना जैसी खूबसूरत जगह हैं।

मुंहासों की समस्या से हैं परेशान? न करें इन 5 चीजों का सेवन

आजकल हर दूसरा व्यक्ति मुंहासों की समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या केवल किशोरावस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई बड़े लोग भी इससे परेशान हैं। त्वचा की देखभाल के साथ-साथ खान-पान का भी इस पर असर पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाने-पीने की चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका ज्यादा सेवन मुंहासों का कारण बन सकता है। इन चीजों से दूरी बनाकर आप मुंहासों से कुछ हद तक राहत पा सकते हैं।

दूध और अन्य डेयरी उत्पाद

दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में मौजूद तत्व और चर्बी मुंहासों के बढ़ने का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको मुंहासों की समस्या है तो दूध, दही, पनीर और मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन कम कर दें। आप चाहें तो इनकी जगह बादाम के दूध, सोया दूध और नारियल के दूध जैसे विकल्पों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो सकता है।

तले हुए खाद्य पदार्थ

तले हुए खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक तेल का इस्तेमाल होता है और तैलीय खाना खाने से शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर बुरा असर पड़ता है। इससे न केवल वजन बढ़ता है, बल्कि चेहरे पर मुंहासे भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको मुंहासों की समस्या है तो तले हुए खाद्य पदार्थों से दूरी बना लें। इसके अतिरिक्त तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन भी कम करें और पानी का भरपूर सेवन करें।

दूध चॉकलेट

दूध चॉकलेट में बहुत अधिक चीनी होती है, जो मुंहासों के कारणों में से एक है। इसका कारण है कि चीनी शरीर में सूजन बढ़ाती है, जिससे मुंहासे होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त चीनी से रक्त शर्करा का स्तर भी बढ़ता है, जिससे इंसुलिन का स्तर भी बढ़ता है और यह इंसुलिन बढ़ने का कारण बनता है। इसलिए मुंहासों से पीड़ति लोगों को चीनी युक्त खाद्य पदार्थों से दूरी बना लेनी चाहिए।

सूखे मेवे

सूखे मेवे को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इनका ज्यादा सेवन भी मुंहासों का कारण बन सकता है। इसका कारण है कि मुंहासे होने का एक कारण शरीर में गर्मी का बढ़ना भी है और सूखे मेवे का ज्यादा सेवन शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से चेहरे पर मुंहासे होने की संभावना अधिक हो जाती है।

बोतलबंद जूस

बोतलबंद जूस को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इनमें मौजूद शक्कर मुंहासों का कारण बन सकती है। इनमें कृत्रिम मिठास होती है, जो न केवल मुंहासों का कारण बन सकती है, बल्कि कई अन्य समस्याओं का भी कारण बन सकती है। इसलिए घर पर फलों का जूस निकालकर पीएं। अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो अनार का जूस पीएं क्योंकि यह मुंहासों की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है।

जीएसटी में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव! आपकी जेब पर ऐसा होगा असर

सरकार जीएसटी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 12% टैक्स स्लैब को खत्म कर 5% या 18% में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। पीएमओ ने मंजूरी दे दी है और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है। इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राज्यों की सहमति के बाद नई दरें लागू होंगी।

देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। खबर है कि सरकार जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में 12% के स्लैब को खत्म करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस बड़े बदलाव को हरी झंडी दे दी है।इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर के मुताबिक जीएसटी लागू होने के आठ साल बाद यह पहला इतना बड़ा कदम होगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। यह बैठक संसद के मानसून सत्र के बाद अगस्त में हो सकती है। आइए, आपको बताते हैं कि इस बदलाव से क्या होगा और इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा।

जीएसटी में बदलाव का क्या है प्लान?

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में 12% टैक्स स्लैब को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अभी जीएसटी में पांच मुख्य स्लैब हैं- 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा सोना-चांदी जैसे बुलियन के लिए 0।25% और 3% के दो खास स्लैब भी हैं। प्रस्ताव है कि 12% स्लैब को खत्म करके इसमें शामिल सामानों को 5% या 18% के स्लैब में शिफ्ट किया जाए। इससे टैक्स सिस्टम को और आसान करने की कोशिश है।

वित्त मंत्रालय इस बदलाव को लागू करने के लिए राज्यों से बातचीत शुरू कर चुका है। मंत्रालय का मकसद सभी राज्यों को इस सुधार के लिए राजी करना है। जीएसटी काउंसिल ही अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) से जुड़े फैसले लेती है, और इसकी अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

जानकारों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद टैक्स स्लैब को कम करना और जीएसटी की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी और ग्राहकों के लिए भी चीजें सस्ती हो सकती हैं। अभी 5% स्लैब में 21% सामान, 12% स्लैब में 19% सामान और 18% स्लैब में 44% सामान आते हैं। सबसे ऊंचे 28% स्लैब में सिर्फ 3% सामान हैं। 12% स्लैब खत्म होने से ज्यादातर सामान या तो 5% में जाएंगे या 18% में, जिससे टैक्स ढांचा और साफ होगा। पिछले कुछ समय से उद्योग जगत जीएसटी में बदलाव की मांग कर रहा है। कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा स्लैब और प्रक्रियाएं जटिल हैं, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। कई सांसदों ने भी संसद में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को उठाया है और इन्हें हल करने की जरूरत बताई है।

अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट

सरकार के बड़े अधिकारियों का मानना है कि जीएसटी को और सरल करने से अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। एक अधिकारी ने कहा, "टैक्स ढांचा अब स्थिर हो चुका है और अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। यह बदलाव करने का सही समय है।" सरकार कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौते) पर काम कर रही है। ऐसे में जीएसटी को आसान करके स्थानीय उद्योगों को पूरा फायदा दिलाने की कोशिश है। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ खास चीजों, जैसे सिगरेट और गाड़ियों, पर 28% टैक्स के साथ मुआवजा उपकर लगाया गया था। यह व्यवस्था जून 2022 तक थी, लेकिन बाद में इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोविड के दौरान राज्यों की ओर से लिए गए 2।69 लाख करोड़ के कर्ज का ब्याज और मूलधन चुकाया जा सके। जीएसटी काउंसिल ने एक अलग मंत्री समूह बनाया है, जो यह तय करेगा कि उपकर निधि में बचे पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा।

कब लागू होंगी नई दरें?

अगर जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो नई दरें जल्द ही लागू हो सकती हैं। हालांकि, इसके लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है। वित्त मंत्रालय इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। साथ ही, इनकम टैक्स कानून में भी बदलाव की तैयारी है, जिसका बिल मानसून सत्र में पेश हो सकता है।

स्ला मॉडल वाई भारत में 60 लाख रुपए में लॉन्च, 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू हो सकती है डिलीवरी

मुंबई, एजेंसी। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने मंगलवार को भारत में अपनी रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) मॉडल वाई कार लॉन्च की, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव की कीमत इसकी वेबसाइट पर पब्लिश्ड प्राइस लिस्ट के अनुसार 67.89 लाख रुपए होगी।

मॉडल वाई की अमेरिका में शुरुआती कीमत 44,990 डॉलर, चीन में 263,500 युआन और जर्मनी में 45,970 यूरो है। भारत में इसकी कीमत किसी भी फेडरल टैक्स प्रोत्साहन से पहले, अमेरिका में इसकी मूल कीमत से लगभग 15,000 डॉलर का अंतर दर्शाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टेस्ला मॉडल वाई शुरुआत में मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगी और इसकी डिलीवरी इस साल की तीसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।

आरडब्ल्यूडी वर्जन के लिए टेस्ला मॉडल वाई की रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किमी होने का दावा किया गया है। लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी वर्जन की रेंज 622 किमी होने का दावा किया गया है।

अपनी फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी के साथ, मॉडल वाई को आरडब्ल्यूडी ट्रिम के लिए 238 किमी और लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी ट्रिम के लिए 267 किमी तक की रेंज जोड़ने में 15 मिनट लगते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मॉडल वाई आरडब्ल्यूडी 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी मॉडल को समान एक्सीलेरेशन के लिए 5.6 सेकंड लगते हैं। दोनों वर्जन की अधिकतम गति 201 किमी प्रति घंटा समान है।

टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई में खुला है, जबकि कंपनी द्वारा नई दिल्ली में दूसरा शोरूम खोले जाने की उम्मीद है। मॉडल वाई शुरुआत में मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगा।

केबिन में 15.4-इंच का फ्रंट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का रियर टचस्क्रीन, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीटे, पावर्ड टू-वे फोल्डिंग और हीटेड सेकंड-रो, फुटवेल और डोर पॉकेट एम्बिएंट लाइटिंग, रैप-अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग और नौ स्पीकर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में टेस्ला के पहले शोरूम 'एक्सपीरियंस सेंटर' का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि टेस्ला मुंबई शहर में आ गई है, जो भारत की न केवल आर्थिक, वाणिज्यिक और मनोरंजन की ही नहीं, उद्यमशीलता की राजधानी भी है।

आयकर विभाग ने कटौतियों और छूटों के फर्जी दावों पर की कार्रवाई : केंद्र

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न (आईटीआर) में कटौती और छूट के फर्जी दावों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर नजर रखना है।

150 कैंपस में चल रहे वेरिफिकेशन अभियान से डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है, जो इन योजनाओं के पीछे के नेटवर्क को खत्म करने और कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

जांच में कुछ आईटीआर तैयार करने वालों और बिचौलियों द्वारा संचालित संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो फर्जी कटौती और छूट का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल कर रहे थे।

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इन धोखाधड़ी वाली फाइलिंग में लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग शामिल है, कुछ लोग अत्यधिक रिफंड का दावा करने के लिए झूठे टीडीएस रिटर्न भी जमा करते हैं।

यह कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लाभों के दुरुपयोग के विस्तृत विश्लेषण के बाद की गई है, जो अक्सर पेशेवर बिचौलियों की मिलीभगत से किया जाता है।

संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिए, आयकर विभाग ने थर्ज पार्टी स्रोतों, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और एडवांस एआई उपकरणों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों का लाभ उठाया है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में हाल ही में की गई तलाशी और जब्ती की कार्रवाइयों से इन निष्कर्षों की पुष्टि होती है, जहां विभिन्न समूहों और संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी के दावों के सबूत पाए गए।

आधिकारिक बयान के अनुसार, विश्लेषण से धारा 10(13ए), 80जीजीसी, 80ई, 80डी, 80ईई, 80ईईबी, 80जी, 80जीजीए और 80डीडीबी के तहत कटौतियों के दुरुपयोग का पता चलता है। बिना किसी वैध औचित्य के छूट का दावा किया गया है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्यमियों के कर्मचारी शामिल हैं।

पिछले एक वर्ष में, आयकर विभाग ने संदिग्ध करदाताओं को अपने रिटर्न संशोधित करने और सही कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने हेतु एसएमएस और ईमेल परामर्श सहित व्यापक संपर्क प्रयास किए हैं। कैंपस के अंदर और बाहर, फिजिकल आउटरीच प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं।

परिणामस्वरूप, पिछले चार महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने अपने रिटर्न अपडेट किए हैं और स्वेच्छा से 1,045 करोड़ रुपये के झूठे दावे वापस ले लिए हैं। हालांकि, कई लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा, आयकर विभाग अब लगातार धोखाधड़ी वाले दावों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

यमन में बैठे इस मौलवी के पास केरल से गया फोन और एक इशारे पर बच गई नर्स निमिषा प्रिया की जान

यमन। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी टल गई है। साथ ही उनकी माफी के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। ये काम केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के हस्तक्षेप की वजह से हुआ है। भारत का यमन में कोई दूतावास नहीं है, ना ही वहां की हूती सरकार को भारत मान्यता देता है। ऐसे में सब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर भारत के ग्रांड मुफ्ती ने कैसे पीड़ित और सरकार से निमिषा प्रिया केस में बातचीत शुरू की।

दरअसल ग्रांड मुफ्ती शेख कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने इस मसले पर यमन के शेख हबीब उमर बिन हाफीज से संपर्क साधा था। शेख हबीब ने ही यमन में अधिकारियों और निमिशा प्रिया द्वारा मारे गए व्यक्ति के रिश्तेदारों के साथ बातचीत शुरू की है। शेख हबीब यमन के एक प्रसिद्ध मौलवी हैं और सूफी संप्रदाय में बा अलावी तरीक़ा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। हबीब उमर यमन के तारिम में एक धार्मिक संस्था 'दार अल-मुस्तफ़ा' के संस्थापक हैं। यमन में युद्ध शुरू होने से पहले कई केरल के कई लोगों ने इस संस्था से पढ़ाई की थी। शेख हबीब के भारत के ग्रांड मुफ्ती अबू बकर के साथ अच्छे रिश्ते हैं।

2007 में आए थे भारत

भारत के ग्रांड मुफ्ती अबू बकर को जॉर्डन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीजसेंटर और अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में रखा गया है। इसी लिस्ट में शेख हबीब भी शामिल हैं। शेख हबीब भारत भी आ चुके हैं। नॉलेज सिटी में मस्जिद और मलप्पुरम में मदीन सदाथ अकादमी के उद्घाटन के मौके पर वह केरल आए थे।

नाम के साथ जुड़े हैं कई बड़े काम

हबीब उमर बिन हाफीज एक यमनी सुन्नी और सूफी इस्लामी विद्वान, शिक्षक और दार अल-मुस्तफ़ा इस्लामी मदरसा के संस्थापक और डीन हैं। वह अबू धाबी में तबाह फाउंडेशन के लिए सर्वोच्च सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। उन्होंने 2007 में 'ए कॉमन वर्ड बिटवीन अस एंड यू' नामक एक मंच बनाया था जो मुसलमानों और ईसाइयों के बीच समन्वय के लिए काम करता है। उनके छात्रों का कहना है कि उन्हें यमन में कुछ चरमपंथी समूहों को छोड़कर, सभी वर्गों में सम्मान प्राप्त है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत-चीन को ट्रंप की सेकेंडरी टैरिफ वाली धमकी.. क्या होगा इसका असर?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने एक बार फिर रूस को टैरिफ धमकी दी है। सोमवार को नोटो सेक्रेटरी मार्क रूट के साथ एक बैठक के बाद ट्रंप ने एक नई योजना का ऐलान किया, जिससे रूस ही नहीं बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले देशों को बड़ा झटका लग सकता है। सोमवार को ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर आने वाले हफ्तों में युद्ध विराम समझौता नहीं होता है, तो वे रूसी सामान खरीदने वाले देशों पर 100 फीसद सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। व्हाइट हाउस में रूट के बगल में खड़े होकर उन्होंने कहा, "हम 100 फीसद टैरिफ लगाने जा रहे हैं... अब समय आ गया है कि वास्तविक बदलाव देखा जाए, वरना इसके परिणाम तत्काल और दर्दनाक होंगे।" नाटो सेक्रेटरी मार्क रूट ने दावा किया कि रूस पर अमेरिका के सेकेंडरी टैरिफ का चीन, भारत और ब्राजील पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे तीनों देश मास्को पर शांति समझौते के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने आगे कहा, "अगर आप बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं, या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह आपको बहुत प्रभावित कर सकता है।" अमेरिका की ओर से अगर सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाता है, तो ये भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में चीन, भारत, ब्राजील, तुर्की और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जिनका व्यापार सालाना सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। ये देश रूसी एनर्जी, फर्टिलाइजर, मेटल्स और रक्षा उत्पादों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

सितंबर में ईरान पर दोबारा हमला? देखिए तीन बड़े सबूत जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं!

वॉशिंगटन, एजेंसी। मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इस बार निशाने पर फिर से ईरान है। संकेत साफ हैं कि ईरान पर सितंबर में फिर से बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। हालात का जायजा लें तो तीन अहम घटनाएं ईशारा कर रही हैं कि दुनिया एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर है। जिसमें अमेरिका की 'अगस्त डेडलाइन', अमेरिका की ईरान से वार्ता करने की जल्दी न होना और भारतीय दूतावास की ईरान से निकलने की एडवाइजरी शामिल है।

जब किसी देश का दूतावास अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह देता है, तो समझ लीजिए कि वहां बड़ा खतरा होने की संभावना है। लेकिन ईरान के मामले में दूतावास ही नहीं कई और संकेत ऐसे मिल रहे हैं, जिनसे लगा है कि यह तुफान से पहले की शांति है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की है। इस बातचीत के बाद यह तय हुआ कि ईरान को अगस्त के आखिर तक समय दिया जाए या तो डील करो या परिणाम भुगतो। यानी ईरान के लिए यह आखिरी मौका है। ईरान को अमेरिका की शर्तों पर झुकना होगा, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण शामिल है। अमेरिकी शर्त नहीं मानने पर हमला होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन लौटते ही प्रेस से बातचीत में कहा कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी है। ट्रंप साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका के दरवाजे पर नहीं आता, तो अमेरिका उसके दरवाज़े पर 'अपने तरीके से' पहुंचेगा। यह 'कोई जल्दी नहीं' असल में एक रणनीतिक चेतावनी है, जैसे शिकारी शांति से बैठा हो, लेकिन निशाना तय कर चुका हो। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को अपनी नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ईरान में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इसराइल-ईरान के बीच जून में हुई जंग के दौरान भारत ने दोनों मुल्कों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिधु लांच किया था। दूसरे देश भी ईरान से अपने नागरिकों को जाने के लिए कह रहे है। जमीनी हालात, खुफिया सूचनाएं, सैन्य तैयारियां और राजनीतिक बयानबाजियां सभी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 11 जुलाई को दुनिया को चौंकाते हुए कहा था कि ईरान के पास 60 दिन हैं, वरना हम इजराइली तरीके से एक्शन लेंगे।

बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे शेख हसीना के लड़ाके, फूंक दी पुलिस की गाड़ी, 3 जवान घायल

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में एक बार फिर जुलाई महीने में बवाल शुरू हो गया है. पिछली बार जुलाई विद्रोह की वजह से शेख हसीना की कुर्सी चली गई थी. हालांकि, इस बार सिनेरियो बदला हुआ है। अब शेख हसीना के लड़ाकों ने ही बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके में हसीना समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी है। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।

द डेली स्टार के मुताबिक बुधवार (16 जुलाई) को बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में एक रैली निकाली। इसी रैली में पुलिस पहुंची, जिस पर बवाल हो गया। देखते ही देखते लीग के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी।

पेट्रोल बम से किया पुलिस पर हमला

बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी और उनसे जुड़े सभी शाखाओं पर बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद बांग्लादेश छात्र आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने यह रैली निकाली है। यह रैली सरकार के विरोध में निकाली गई है। शेख हसीना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है।

हाल ही में शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपने समर्थकों से बात की थी। शेख हसीना का कहना था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी है और उनके लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। हसीना ने लोगों से लड़ाई न रोकने की अपील की थी।

स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक बुधवार को रैली में लीग के कार्यकर्ता पेट्रोल बम लेकर पहुंचे थे। जैसे ही विरोध की स्थिति बनी, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर बम फेंक दिया। गाड़ी वहीं पर खाक हो गई है। हमले की वजह से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।

हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल

शेख हसीना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जो अटैक किया है। उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। दरअसल, 16 जुलाई से एनसीपी समेत कई पार्टियां जुलाई विद्रोह के एक साल पूरे होने पर जश्न कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ऐसे में जिस तरीके से यह अटैक हुआ है, उससे सवाल उठ रहे हैं।

बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में बीबीसी बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरीके से शेख हसीना के लोग एक्टिव हो रहे हैं, वो चिंताजनक है। बांग्लादेश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे और यहां इससे तनाव बढ़ेगा।

बांग्लादेश में गिरा दिया गया सत्यजीत रे का घर, भारत ने कहा था हम करेंगे मरम्मत, रखा जाए संरक्षित

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश में भारतीय फिल्ममेकर सत्यजीत रे का घर गिरा दिया गया है। सत्यजीत रे का यह घर बांग्लादेश में मैमनसिंह शहर में मौजूद था। इसे पहले मैमनसिंह शिशु अकादमी के नाम से जाना जाता था। भारत इस इमारत को संरक्षित करना चाहता था। इसी के चलते भारत ने इमारत की मरम्मत और पुनर्निर्माण की बांग्लादेश को पेशकश भी की थी। इस इमारत को संरक्षित करने के लिए कहा था। लेकिन, इसके बावजूद भी फिल्ममेकर का पैतृक घर गिरा दिया गया है। प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी, प्रसिद्ध कवि सुकुमार रे के पिता और फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के दादा थे, जो इसी घर में रहते थे। अब इस इमारत को गिरा दिया गया है। फिल्ममेकर सत्यजीत रे के घर की मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग करने की भारत ने पेशकश की थी। 100 साल पुरानी इस इमारत पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है, इसी के चलते इसकी हालत खराब हो गई है। भारत ने इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण करने की पेशकश की थी। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह अफसोसनाक है कि मैमनसिंह में वो संपत्ति, जो कभी फिल्ममेकर रे के दादा की थी उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस इमारत को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी पोस्ट सामने आया था। इसी के बाद अब जब घर गिरा जा चुका है तो इसी को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुझे यह जानकर बेहद दुख हुआ है कि ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर सत्यजीत रे का ढाका में मौजूद पैतृक घर को कथित तौर पर बांग्लादेशी अधिकारी ध्वस्त कर रहे हैं। यह 100 साल पुरानी संपत्ति रे के दादा, उपेंद्रकिशोर रे चौधरी की थी, जो बंगाली साहित्य और संस्कृति के एक दिग्गज थे। उन्होंने आगे कहा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजर से यह बेहद जरूरी स्थल था जिसको खंडहर में तब्दील करना हमारी विरासत पर एक आघात से कम नहीं है। यह वैश्विक कला में रे परिवार के योगदान को मिटाने जैसा है।

बांग्लादेश सरकार से पूछे सवाल

टीएमसी नेता ने कहा, मैं बांग्लादेश सरकार से आग्रह करता हूं कि वो इस कठोर निर्णय पर पुनर्विचार करें। इस सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाए। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं कि वह उचित द्विपक्षीय सहयोग शुरू करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बंगाल के सांस्कृतिक इतिहास की यह धरोहर विध्वंस के कारण नष्ट न हो।

"बंगाली विरासत को एक और झटका"

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, बंगाली विरासत को एक और झटका – सत्यजीत रे का पैतृक घर बांग्लादेश में ध्वस्त कर दिया गया। यह सिर्फ एक पुरानी संरचना का विनाश नहीं है – यह इतिहास को मिटाना है। जिस मिट्टी ने दुनिया के महानतम सिनेमाई फिल्ममेकर में से एक को बढ़ा किया, वह अब मलबे में बदल गई है। क्या बांग्लादेश सरकार को ऐसे विशाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य वाले स्थल को संरक्षित करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी?

जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान तेज, पुराने सुरक्षा पिकेट्स को किया जा रहा फिर से तैनात

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने एक बार फिर बड़ा आतंक विरोधी अभियान छेड़ दिया है। आतंकियों की बढ़ती हलचल के इनपुट के बाद किश्तवाड़ जिले के दुर्गम इलाकों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं, राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जैसे संवेदनशील पहाड़ी जिलों में पुराने सुरक्षा पिकेट्स को दोबारा स्थापित करने की कवायद तेज कर दी गई है।

किश्तवाड़ के वारवन क्षेत्र के चोईडरमन, बसमिना और सुखनाई गांवों में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। खुफिया जानकारी के अनुसार, इन इलाकों में 3 से 4 संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने इलाके को घेरकर तलाशी तेज कर दी है।

इस ऑपरेशन का नेतृत्व एसएसपी किश्तवाड़ नरेश सिंह की निगरानी में SDPO मारवाह विजय कुमार भगत और SHO वारवन दानिश अमीन कर रहे हैं। तलाशी के दौरान सुरक्षा बल खाली पड़े ढोक मकानों की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी यह ही मिली है कि आतंकी इन्हीं जगहों को छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

खास बात यह है कि जिस सुखनाई क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं से पहलगाम और शीशनाग की ओर जाने वाला एक ट्रैकिंग रूट भी गुजरता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं ताकि नागरिकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जम्मू संभाग के ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा पिकेट्स को दोबारा स्थापित किया जा रहा है। ये वही पिकेट्स हैं जो 2003-2004 तक सक्रिय थीं, लेकिन आतंकवाद में कमी आने के बाद हटा दी गई थीं। अब दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर इन सुरक्षा चौकियों को दोबारा चालू किया जा रहा है। सेना सूत्रों के मुताबिक, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी और उधमपुर जिलों में फिलहाल 50 से 60 आतंकियों की सक्रियता के इनपुट हैं। इनमें अधिकतर आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं और छोटे-छोटे ग्रुपों में बंटकर गतिविधियां कर रहे हैं।

वोटर लिस्ट से नाम काटने के पहले चुनाव आयोग देगा मौका

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता पुनरीक्षण अपडेट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो वहीं चुनाव आयोग इसको लेकर एक और नया अपडेट जारी किया है। इस नए अपडेट में आयोग ने बताया कि नाम कटने से पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ ही दस्तावेज देने का मौका दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदाता पुनरीक्षण अपडेट में मतदाताओं को पहले

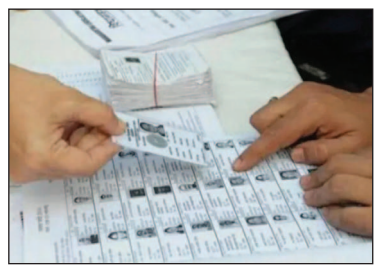

नोटिस दिया जाएगा। आयोग मतदाता सूची से नाम काटने के पहले नोटिस भेजेगा। इसके साथ ही 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले प्रारूप में किसी का नाम नहीं काटा जाएगा।

आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा। गणना प्रपत्र जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम प्रारूप प्रकाशन में शामिल होगा।

BLO कर रहे लापरवाही

मतदाता पुनरीक्षण मामले में BLO की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इनकी लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि कई बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) सभी के घर नहीं जा रहे हैं, खुद फॉर्म भर रहे हैं, और आवश्यक दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं। कई जगहों पर केवल अंगूठा लगवाकर सत्यापन किया जा रहा है, और मोबाइल पर दस्तावेज देखकर भी सत्यापन हो रहा है। अब तक सौ से ज्यादा BLO पर कार्रवाई की जा चुकी है। अकेले पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में ही 35 BLO के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पुनरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा

इस पुनरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कई जिलों, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए गए हैं। इससे सियासी माहौल गरम हो गया है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं और फर्जी मतदाताओं को बख्शा नहीं जाने की चेतावनी दी है। 31 जुलाई 2025 तक मतदाता सूची में सुधार कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

Prabhas की 900 करोड़ी एक्ट्रेस ने कही ऐसी बात, सुनकर दीपिका पादुकोण को हो सकता है पछतावा!

दीपिका पादुकोण की एग्जिट के बाद प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में तृप्ति डिमरी की एंट्री हो चुकी है। 'एनिमल' के बाद एक बार फिर से तृप्ति डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करने जा रही हैं। अब उन्होंने फिल्म को लेकर खुलकर बात की है।

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट करने की मांग पर हर तरफ चर्चा जारी है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की गद्दी पर कब्जा किए बैठीं दीपिका की डिमांड के चलते उन्हें 300 करोड़ी फिल्म से बाहर होना पड़ा। एक्ट्रेस की शर्त थी कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। बस फिर क्या था डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी बिना वक्त गंवाए अपनी फिल्म 'स्पिरिट' के लिए झट से नई हीरोइन तलाश कर ली। ये नई एक्ट्रेस भले ही फिल्म के लिए हैं, लेकिन संदीप के लिए उनकी पुरानी एक्ट्रेस हैं। 'एनिमल' के जरिए तृप्ति डिमरी की किस्मत चमकाने वाले संदीप ने 'स्पिरिट' के लिए भी उन्हें ही फाइनल कर लिया। अब तृप्ति ने 'स्पिरिट' में काम करने के बारे में खुलकर बात की है।

दीपिका पादुकोण की जगह लेने के बाद से ही तृप्ति डिमरी सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं, एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'धड़क 2' की रिलीज़ की तैयारी में भी जुटी हैं। बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में तृप्ति डिमरी ने बताया कि कैसे उन्होंने अलग-अलग कैटेगरी और इंडस्ट्री के कुछ बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करके अपने करियर को आगे बढ़ाया है। एक्ट्रेस ने कहा, "हां, अलग-अलग निर्देशकों के साथ काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हैं।"

तृप्ति डिमरी के हाथ लगी 300 करोड़ी फिल्म

तृप्ति डिमरी ने कहा, "हर फिल्ममेकर अपनी संवेदनशीलता और अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाता है और यह आपको खुद ही आगे बढ़ने और ग्रो करने के लिए हौसला देता है। मैं अभी विशाल के साथ काम कर रही हूं, और वह फिल्म भी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, इसलिए मैं उसे लेकर काफी एक्साइटेड हूं। उसके बाद, जाहिर तौर पर मिस्टर वांगा की 'स्पिरिट' आएगी और मैं इसे लेकर भी बहुत खुश हूं।" बता दें इस फिल्म का बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है।

'स्पिरिट' पर तृप्ति डिमरी ने की खुलकर बात

जबकि संदीप रेड्डी वांगा फिल्म के बारे में बात करते हुए तृप्ति ने कहा, "यह एक खूबसूरत फिल्म है।" 'स्पिरिट' प्रभास और तृप्ति डिमरी की पहली ऑन-स्क्रीन फिल्म होगी और 'एनिमल' के बाद निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा और निर्माता भूषण कुमार और प्रणय रेड्डी वांगा के साथ उनका दूसरा प्रोजेक्ट होगा। फिल्म में प्रभास एक क्रूर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाले हैं और 2025 में इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।

हमारा दिल खुशियों से भर गया', सिड-कियारा ने दी बेटी के जन्म की जानकारी; फैंस ने दी बधाई

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपने पैरेंट्स बनने की जानकारी अब अपने फैंस के साथ शेयर की है।

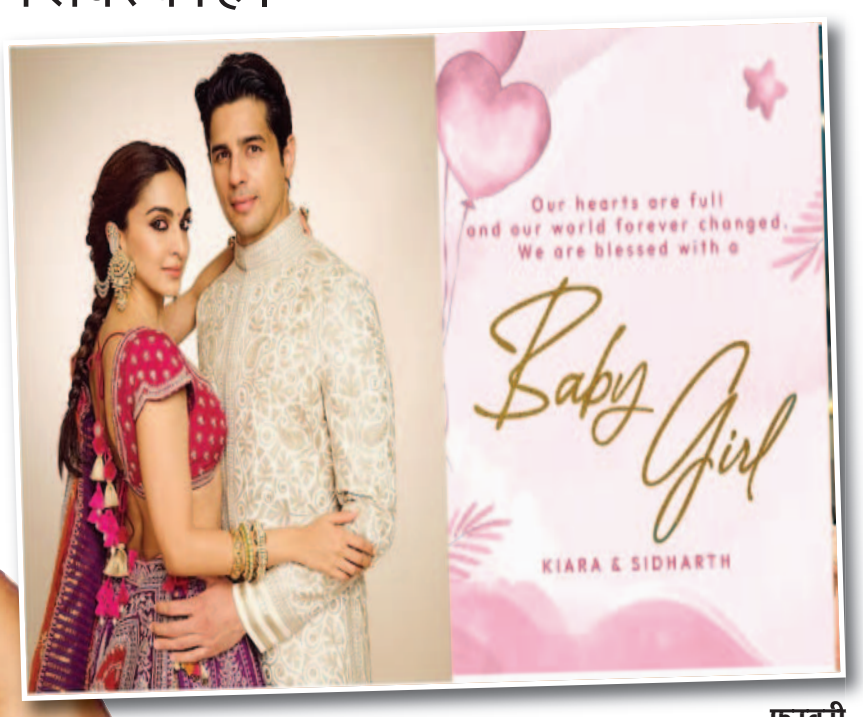

बॉलीवुड के लवली कपल में शामिल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के घर नन्ही परी आई है। कपल ने अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। इसके बाद फैंस दोनों को बधाइयां दे रहे हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के बेटी होने की खबर कल रात सामने आई थी। अब आज कपल ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो एक प्यारी सी बेटी के पैरेंट्स बन गए हैं। सिद्धार्थ और कियारा ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में लिखा है, 'हमारे दिल खुशियों से भरे हैं और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। हमें बेटी की प्राप्ति हुई है।' पोस्ट में नीचे सिद्धार्थ और कियारा के नाम लिखे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में सिद्धार्थ ने सिर्फ दिल, नजर और हाथ जोड़े वाले इमोजी का इस्तेमाल किया है।

फरवरी में अनाउंस की थी प्रेग्नेंसी

इसी साल फरवरी में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने फैंस को ये खुशखबरी दी थी कि दोनों जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को इस बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद कियारा बेबी बंप के साथ मेट गाला में रेट कार्पेट पर उतरी थीं।

फरवरी

2023 में हुई थी दोनों की शादी

सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी 'शेरशाह' फिल्म की शूटिंग के दौरान चर्चा में आई थी। दोनों को इसके बाद कई मौकों पर साथ देखा गया था। हालांकि, दोनों ने अपने अफेयर को लेकर कभी खुलकर कोई बात नहीं की थी। इसके बाद फरवरी 2023 में दोनों शादी के बंधन में बंधे थे।

'वॉर 2' में नजर आएंगी कियारा

वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी जल्द ही 'वॉर 2' में नजर आएंगी। यह यशराज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के टीजर में ही कियारा बिकनी लुक काफी वायरल हुआ था।

'परम सुंदरी' में दिखाई देंगे सिद्धार्थ

वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर जल्द ही दिनेश विजन की फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ जान्हवी कपूर प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म के अगस्त में रिलीज होने की उम्मीद है। इसके अलावा वो 'वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म में भी नजर आएंगे।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com